www.ghoonghatkibagawat | www.ghoonghatkibagawat | ghoonghatkibagawat37@gmail.com

घूँघट की बगावत

UP/HIN/1999/1282

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित

हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष : 24 अंक : 26 | गोरखपुर, 05 जनवरी 2025 रविवार | पृष्ठ : 6 | मूल्य : 2

राजस्थान सरकार का जोखिम भरा और सराहनीय कदम

राजनीतिक लाभ हानि से जुड़े निर्णयों को बदलना किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए जोखिम से कम नहीं होता। इस तरह के निर्णय करने में सरकारों को काफी संकोच करना पड़ता है क्योंकि किसी भी निर्णय को बदलते समय राजनीतिक गुणाभाग देखा जाता है और यही कारण है कि कई निर्णय ऐसे होते हैं जिनके लाख चाहने और प्रशासनिक दृष्टि से सही नहीं होने पर भी सरकारें ढ़ोये जाती है। इस मायने में राजस्थान की सरकार की सराहना करनी पड़ेगी कि राजनीतिक दृष्टि से निर्णय लेना मुश्किल व जोखिम भरा होने के बावजूद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पूर्व सरकार के समय के जिले बनाने के निर्णय का परीक्षण कर 9 जिले और 3 संभाग समाप्त करने का निर्णय लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अब प्रदेश में 41 जिले और 7 संभाग रह गए हैं। दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीम का थाना, अनूपगढ़, गंगापुरसिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण और सांचौर जिला और बांसवाड़ा, सीकर और पाली संभाग को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। निश्चित रुप से शुरूआत में इसका विरोध होगा, राजनीति से जुड़े लोगों द्वारा हवा भी दी जाएगी पर जब कोई दूरगामी जनहित का निर्णय लिया जाता है तो देर सबेर जनता उसे स्वीकार्य भी कर लेती है। राज्य सरकार द्वारा यही निर्णय नई सरकार बनते ही लिया जाता तो उसके मायने कुछ अलग होते और उस पर राजनीतिक द्वेषता का ठप्पा लगता वह अलग होता। आज भले ही विपक्ष द्वारा इस निर्णय पर प्रश्न उठाये जा रहे हो पर सही मायने में देखा जाए तो यह पूरी तरह से प्रशासनिक निर्णय है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पूर्व सरकार के नए जिले बनाने के निर्णय का परीक्षण करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी डा. ललित पंवार की अध्यक्षता में समिति गठित कर परीक्षण करवाया और फिर राजनीतिक स्तर पर मंत्रीमण्डलीय समिति बनाकर सभी पक्षों का अध्ययन कर रिपोर्ट आने पर मंत्रीमण्डल की बैठक में मोहर लगाई गई। इसलिए एक बात तो साफ हो जानी चाहिए कि यह निर्णय किसी भी मायने में जल्दबाजी या राजनीतिक लाभ के लिए ना होकर पूरी तरह से प्रशासनिक दक्षता के लिए लिया गया निर्णय है। ना ही इसे जल्दबाजी में लिया निर्णय कहा जा सकता है। हांलाकि पूर्व सरकार ने नए जिले बनाने के लिए भले ही प्रशासनिक कमेटी बनाकर रिपोर्ट प्राप्त कर नए जिले बनाने का निर्णय किया पर यह सब अच्छी तरह से साफ हो जाना चाहिए कि चुनाव नजदीक होने के कारण पूर्व सरकार द्वारा नए जिले बनाने के निर्णय को आमलोगों ने पूरी तरह से राजनीतिक निर्णय के रुप में ही देखा गया।

भजन लाल शर्मा ने पूर्व सरकार द्वारा गठित नए जिलों के गठन का प्रशासनिक दृष्टि से परीक्षण करवाया और इसमें कोई दो राय नहीं कि शुरूआत में इन जिलों और संभागों को समाप्त करने के निर्णय का विरोध हो पर यह विरोध इसलिए अधिक असर नहीं दिखा पाएगा कि आम नागरिक यह अच्छी तरह से समझता है कि अधिक और छोटे जिले बनने से सरकारी खर्चे अधिक बढ़ने के अलावा कोई खास प्राप्त होने वाला नहीं है। नए जिलों के लिए शुरूआती दौर में ही एक जिले के लिए कम से कम एक हजार करोड़ की व्यवस्था करनी होगी। जिला कलक्टर और जिला पुलिस एसपी के दफ्तर तो तत्काल शुरू करने के साथ ही अन्य विभागों के भी दफ्तर जिला स्तर पर खोलने से ही वास्तविक लाभ प्राप्त हो सकता है। अब इसे यों देखा जाए कि इस सबके लिए कितना बड़ा प्रशासनिक अमला तैयार करना होगा, कितनी अधिक आधारभूत सुविधाएं विकसित करनी होगी। सरकारी ऑफिस, सरकारी बंगले और ना जाने कितने ही कार्यों के लिए स्थान और आधारभूत संरचना विकसित करने के साथ ही अधिकारियों-कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी। इसके साथ ही अन्य सुविधाएं और अन्य सेवाएं अलग होगी। हमारे सामने पुराने उदाहरण है जब राजसमंद, प्रतापमढ़, दौसा जिले बनाए गए और करौली व प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया। अब सबके सामने है कि इन जिलों को सही मायने में जिलो का आकार लेने में कितना समय लगा। आज भी कई स्थानों पर फिजिबल नहीं होने के कारण जिला सहकारी बैंक नहीं खुल पाएं है तो कई अन्य सरकारी दफ्तर शुरू नहीं हो पाये हैं। दरअसल जन हितकारी सरकार की पहचान लोकहित में दूरगामी परिणामों को देखते हुए निर्णय लेना होता है। हांलाकि लोकतंत्र में बहुत से निर्णय राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण न चाहते हुए भी लेने होते हैं तो कई बार ऐसा भी लगता है कि ऐन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह के निर्णय ले लिए जाते हैं।

प्रशासनिक दक्षता और लोकहितकारी सरकार की पहचान जनहित में कड़बे निर्णय लेने में भी संकोच नहीं करना होता है। सरकार की संवेदनशीलता और प्रशासनिक दक्षता का भी इसी से पता चलता है। खासतौर से राजनीतिक लाभ हानि से लिए गए निर्णय से अधिक भला नहीं हो पाता है। सरकार की प्रशासनिक और लोकहितकारी होने का इसी से पता चलता है कि वह जनहित में जोखिम भरे निर्णय लेने में भी कोई संकोच ना करें। लोकतंत्र में जनता और जनता का हित बड़ी बात होनी चाहिए क्योंकि सरकार द्वारा निर्णयों का असर दूर तक जाता है। कड़बे निर्णय यदि लोकहित में होते हैं तो जनता ऐसे निर्णयों को हाथोंहाथ लेती है। इसलिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सरकार बनने के पहले साल में ही बड़े निर्णय कर सबको चौंका दिया है। राजनीतिक लाभ हानि से परे हटकर मुख्यमंत्री ने 9 जिले और 3 संभाग समाप्त करने का निर्णय व्यापक जनहित में ही देखा जाना चाहिए। आर्थिक विश्लेषकों को मानना है कि सरकार को अपने प्रशासनिक खर्चों को एक सीमा तक रखना चाहिए। हांलाकि सब कुछ जानते हुए भी होता इसके विपरीत ही है। सरकार राजस्व का अधिकांश खर्चा अपने प्रशासनिक दायित्वों वेतन-सुविधाओं में ही खर्च कर देती है वहीं नए जिले और संभाग बनने से प्रशासनिक खर्च बढ़ना स्वाभाविक है। दूसरी बात यह है कि नए जिले या संभाग बनाने के स्थान पर सरकारों को प्रशासनिक सेवाओं में सुधार और डिलीवरी सिस्टम को मजबूत बनाने पर जोर देना चाहिए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजनीतिक जोखिम लेते हुए प्रशासनिक दृष्टि से सराहनीय निर्णय किया है। इससे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उनकी सरकार ने प्रशासनिक दृष्टि से परिपक्वता का परिचय दिया है। हो सकता है कि निर्णय को लेकर विरोध देखने को मिले पर विरोध के खिलाफ भी सरकार को सख्ती दिखानी होगी इससे आमजन में सरकार और सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों को सराहा ही जाएगा। सरकारों को राजनीतिक लाभ हानि के साथ ही व्यापक जनहित को भी ध्यान देना चाहिए और निर्णय लेने में किसी तरह का संकोच नहीं करना चाहिये।

पार्षद दुलाल सरकार हत्याकांड प्रकरण: तीन गिरफ्तार, पुलिस को अब मास्टरमाइंड की तलाश

पश्चिम बंगाल। पुलिस ने मालदा में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पार्षद दुलाल सरकार की हत्या के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने कहा कि हत्या पूर्व नियोजित थी, पहले से व्यापक टोह ली गई थी। सरकार, जिसे बबला के नाम से भी जाना जाता है, की गुरुवार सुबह बाइक सवार लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज में दो हमलावरों को टीएमसी नेता पर गोलियां चलाते हुए दिखाया गया है, क्योंकि वह एक कार्यालय में भागने का प्रयास कर रहे थे। गोलीबारी के बाद हमलावर तुरंत भाग निकले।

गिरफ्तार किए गए तीन संदिग्धों को शुक्रवार को मालदा जिला अदालत में पेश किया गया, जिनमें दो बिहार के और एक मालदा के इंग्लिश बाजार शहर का है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपी कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं। अधिकारियों ने अदालत को सूचित किया कि हत्या के पीछे का कथित मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। जांचकताओं ने संदिग्धों से आगे की पूछताछ के लिए 14 दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की। अदालत के एक अधिकारी ने कहा कि मालदा बार एसोसिएशन का कोई भी निजी वकील आरोपी की ओर से पेश नहीं हुआ।

मालदा जिला कानूनी सहायता के माध्यम से कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, जिसने उनके लिए जमानत याचिका दायर की। हालांकि, न्यायाधीश रतन कुमार गुप्ता की अध्यक्षता वाली अदालत ने याचिका खारिज कर दी और तीनों को 14 दिन की पुलिस रिमांड का आदेश दिया। इस बीच, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हत्या को लेकर अपने ही पुलिस बल पर निशाना साधा और मालदा के पुलिस अधीक्षक की निंदा की। बनर्जी ने कहा कि दुलाल सरकार की सुरक्षा हाल ही में वापस ले ली गई थी। ऐसी लापरवाही कैसे हो सकती है? यह अस्वीकार्य है।

नव वर्ष-2025 की हार्दिक शुभ कामनाएं

प्रिय पाठकों, संवाद दाताओं
एवं पत्र से जुडे सभी स्वतंत्र लेखकों
आप सभी को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभ कामनाएं। यह वर्ष आप सभी की जिन्दगी को एक नई गतिशीलता प्रदान करे आपके अधूरे स्वप्नों को साकार करने का संबल बने। आप निरंतर प्रति पथ पर निष्कंटक गतिमान रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका

घूँघट की बगावत
हिन्दी साप्ताहिक परिवार

महाकुम्भ के दौरान अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को न हो असुविधा: सीएम योगी

अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को भाजपा कार्यकताओं से बैठक के उपरांत प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज के सभागार में जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने महाकुम्भ-2025 के दौरान अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, क्लाइड मैनेजमेंट, आश्रय स्थल आदि को लेकर जानकारी हासिल की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज महाकुम्भ-2025 में 40-45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसमें से अधिकांश श्रद्धालु अयोध्या भी आएंगे। यहां श्रद्धालु रामलला, हनुमानगढ़ी, सूर्यकुंड समेत अनेक मंदिरों व स्थलों पर दर्शन करेंगे। स्थानीय प्रशासन दर्शनार्थियों की सुरक्षा, क्लाउड मैनेजमेंट, दर्शन-पूजन, आश्रय स्थल आदि को लेकर सारी तैयारी पूर्ण कर ले। ठंड के मौसम में किसी भी श्रद्धालु को यहां परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता पर जोर दिया। साथ ही कहा कि यहां अलाव आदि की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। मंडलायुक्त गौरव दयाल ने महाकुम्भ-2025 के संबंध में अयोध्या में होने वाली तैयारियों को लेकर प्रस्तुतिकरण भी दिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। समीक्षा बैठक में स्थानीय प्रशासन, पुलिस व जिले के आलाधिकारी उपस्थित रहे।

मुस्लिम समाज की पहल से बनेगा भारत सांप्रदायिक सौहार्द्र का वैश्विक प्रतीक: इंद्रेश कुमार

लखनऊ। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम) उत्तर प्रदेश की एक ऐतिहासिक बैठक गांधी स्मृति हाल, कैसरबाग में आयोजित हुई। इस कार्यक्रम ने सांप्रदायिक सौहार्द्र और धार्मिक संवाद की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाते हुए विवादित धार्मिक स्थलों पर समाधान खोजने का आह्वान किया गया। इस मौके पर संघ के वरिष्ठ नेता और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश के मुसलमानों को राष्ट्रहित में आगे आना होगा। काशी, मथुरा और सम्भल के विवाद पर इंद्रेश कुमार ने कहा कि मुस्लिम समाज को पहल दिखानी होगी और कुरान और हदीस की रोशनी में बड़े फैसले करने होंगे।

मुख्य वक्ता और मंच के मार्गदर्शक डॉ. इंद्रेश कुमार ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम समाज अपनी जिम्मेदारी समझे और संवाद से काशी, मथुरा और सम्भल जैसे स्थलों पर विवाद खत्म करे। इस्लाम में जबरन कब्जे की इजाजत नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि धर्म के नाम पर कब्जा और हिंसा इस्लामिक उसूलों के खिलाफ हैं। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से इन स्थलों को हिंदू समाज को सौंपने की अपील की, ताकि भारत सांप्रदायिक सौहार्द्र का वैश्विक उदाहरण बने। साथ ही साथ इंद्रेश कुमार ने कहा कि मुसलमानों को वैसी पार्टियों और संगठनों को पहचान कर दूरी बनानी होगी जो उन्हें वोट बैंक समझ कर बेचने, बहकाने, बरगलाने और लड़ाने का काम करते हैं।

डॉ. कुमार ने धार्मिक विवादों को हल करने के लिए मुस्लिम समाज से आत्ममंथन और संवाद की पहल करने को कहा। उन्होंने कुरआन और हदीस का हवाला देते हुए कहा कि जबरन कब्जे की जमीन पर बनी मस्जिदें नाजायज हैं। इस्लाम अमन और इंसाफ का मजहब

है। विवादों का हल संवाद और सहमति से निकाला जाना चाहिए।

बैठक में वक्फ संपत्तियों पर हो रहे कब्जों और उनके सही उपयोग पर चर्चा हुई। डॉ. कुमार ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि यह कानून मुस्लिम समाज की भलाई और पारदर्शिता के लिए है। वक्फ संपत्तियों को समाज सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए उपयोग में लाना चाहिए।

बैठक में मंच के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफजाल, सैयद रजा हुसैन रिजवी, डॉ. शालिनी अली, इस्लाम अब्बास, ठाकुर राजा रईस, डॉ. ताहिर शाह, तुषारकांत, आलोक चतुर्वेदी, डॉ. अली जफर, फरीद साबरी, डॉ. अनिल सिंह, डॉ. रिजवाना, कोमल नेहा, रुखसाना नकवी, गौसिया खानम, शेर खान, कौसर जहां, डॉ. तौकीर खान, और फिरोज अब्बासी समेत 700 से अधिक लोगों ने भाग लिया। मंच का संचालन राजा हुसैन रिजवी ने करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें रखीं जो मुस्लिम समाज के लिए काफी अहम हैं। उनके अलावा शिक्षाविदों, मुफ्तियों, मौलानाओं और बुद्धिजीवियों ने भी विचार साझा करते हुए सांप्रदायिक सौहार्द्र को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए।

डॉ. कुमार ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम समाज को भारत की एकता और अखंडता के लिए नेतृत्व करना होगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का यह उद्देश्य है कि भारत सांप्रदायिक सौहार्द्र, विकास और अमन का वैश्विक आदर्श बने। यह तभी संभव है जब हम पुरानी गलतियों से सबक लेकर समाधान के रास्ते पर बढ़ें। यह बैठक एक स्पष्ट संदेश लेकर आई कि अब मुस्लिम समाज को विवादों को सुलझाने में पहल करनी होगी और भारत को सांप्रदायिक सद्भाव का विश्व आदर्श बनाना होगा।

प्रधानमंत्री मोदी के अजमेर दरगाह पर चादर भेजने से कोई फायदा नहीं: ओवैसी

जयपुर (अजमेर)। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अजमेर दरगाह पर चादर भेजे जाने से कोई फायदा नहीं है और सरकार को मौजूदा मस्जिदों या दरगाहों को लेकर अदालतों में दायर किए जा रहे दावों को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि चादर भेजने के पीछे संदेश यह है कि सरकार मस्जिदों में आस्था रखने वालों की फिक्र करती है, लेकिन भाजपा और संघ परिवार के लोग यह कहते हुए अदालतों में जा रहे हैं कि ख्वाजा अजमेर की दरगाह कोई दरगाह नहीं है, जैसा कि उनका कुछ मस्जिदों के मामले में तर्क है।

ओवैसी ने कहा कि सरकार का असली काम ऐसे दावों को खत्म करना है। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरण रीजीजू ने शनिवार को सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ह्यउर्सह्ल पर अजमेर दरगाह पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भेजी गई चादर चढ़ाई। मोदी द्वारा चादर भेजे जाने के बारे में पूछे जाने पर ओवैसी ने कहा कि भाजपा और संघ परिवार से जुड़े लोग इस दावे के साथ देश में कई स्थानों पर खुदाई की मांग करते हुए अदालतों का रुख कर रहे हैं कि मौजूदा मस्जिद या दरगाह कोई मस्जिद या दरगाह नहीं हैं। उन्होंने कहा, ह्यह्यअगर प्रधानमंत्री चाहें तो ये सब चीजें बंद हो जाएंगी।

ओवैसी ने कहा कि मस्जिदों से जुड़े सात से अधिक ऐसे मुद्दे भाजपा शासित उत्तर प्रदेश से हैं। दो काउंटी की स्थापना पर केंद्र द्वारा चीन के समक्ष विरोध दर्ज कराए जाने पर ओवैसी ने कहा कि सरकार चीन से निवेश चाहती है और पड़ोसी देश के साथ आयात असंतुलन को सहन कर रही है।

उन्होंने कहा, ह्यह्ययह सरकार चीन से डरती है। कैसा विरोध? वे (चीन) हमारी जमीन पर काउंटी, बांध बना रहे हैं? अगर बांध बन गया तो किसे नुकसान होगा।

चार लोगों को घायल करने वाले तेंदुए की मौत

महराजगंज। उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में एक तेंदुए ने शनिवार को चार लोगों पर हमला कर दिया हालांकि हमले के बाद बेहोश हुए तेंदुए की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गयी। वन विभाग के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि शनिवार सुबह महराजगंज के सोहगीबरवा वन्यजीव अभयारण्य के मझौली गांव के पास एक मस्जिद में तेंदुआ घुस गया और उसने चार लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। उन्होंने बताया कि चार लोगों पर हमला करने के बाद तेंदुए को कुछ ग्रामीणों ने पकड़ लिया। अधिकारी ने बताया कि पकड़े जाने के बाद तेंदुआ बेहोश हो गया और बाद में अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गयी। महाराजगंज के प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) निरंजन सुर्वे ने पत्रकारवार्ता के दौरान को बताया कि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आयेगा और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

कर्म से परिवर्तन

विजय गर्ग

एक राजा अपनी प्रजा का भरपूर ध्यान रखता था. राज्य में अचानक चोरी की शिकायतें बहुत आने लगीं. कोशिश करने से भी चोर पकड़ा नहीं गया। हारकर राजा ने ढींढोरा पिटवा दिया कि जो चोरी करते पकड़ा जाएगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा. सभी स्थानों पर सैनिक तैनात कर दिए गए. घोषणा के बाद तीन-चार दिनों तक चोरी की कोई शिकायत नहीं आई। उस राज्य में एक चोर था जिसे चोरी के सिवा कोई काम आता ही नहीं था. उसने सोचा मेरा तो काम ही चोरी करना है. मैं अगर ऐसे डरता रहा तो भूखा मर जाऊँगा. चोरी करते पकड़ा गया तो भी मरुंगा, भूखे मरने से बेहतर है चोरी की जाए। वह उस रात को एक घर में चोरी करने घुसा. घर के लोग जाग गए. शोर मचाने लगे तो रिक्त हाथ ही चोर भागा. पहरे पर तैनात सैनिकों ने उसका पीछा किया. चोर जान बचाने के लिए नगर के बाहर भागा। उसने मुड़ के देखा तो पाया कि कई सैनिक उसका पीछा कर रहे हैं. उन सबको चमका देकर भाग पाना संभव नहीं होगा. भागने से तो जान नहीं बचने वाली, युक्ति सोचनी होगी। चोर नगर से बाहर एक तालाब किनारे पहुंचा. वस्त्र उतारकर तालाब मे फेंक दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर एक बरगद के पेड के नीचे पहुंचा। बरगद पर बगुलों का वास था. बरगद की जड़ों के पास बगुलों की बीट पड़ी थी. चोर ने बीट उठाकर उसका तिलक लगा लिया ओर आंख मूंदकर ऐसे स्वांग करने बैठा जैसे साधना में लीन हो। खोजते-खोजते थोडी देर मे सैनिक भी वहां पहुँच गये। पर उनको चोर कहीं दिखाई नहीं आ रहा था. खोजते खोजते उजाला हो रहा था ओर उनकी दृष्टि बाबा बने चोर पर पडी। सैनिकों ने पूछा- बाबा इधर किसी को आते देखा है. पर ढोंगी बाबा तो समाधि लगाए बैठा था. वह जानता था कि बोलूंगा तो पकडा जाउंगा सो मौनी बाबा बन गया और समाधि का स्वांग करता रहा। सैनिकों को कुछ शंका तो हुई पर क्या करें। कही सही में कोई संत निकला तो ? अंततः उन्होंने छुपकर उस पर नजर रखना जारी रखा. यह बात चोर भांप गया। जान बचाने के लिए वह भी चुपचाप बैठा रहा। एक दिन, दो दिन, तीन दिन बीत गए बाबा बैठा रहा. नगर में चर्चा शुरू हो गई की कोई सिद्ध संत पता नही कितने समय से बिना खाए-पीए समाधि लगाए बैठे हैं. सैनिकों को तो उनके अचानक दर्शन हुए हैं। नगर से लोग उस बाबा के दर्शन को पहुंचने लगे। भक्तों की अच्छी खासी भीड़ जमा होने लगी. राजा तक यह बात पहुंच गई। राजा स्वयं दर्शन करने पहुंचे. राजा ने विनती की आप नगर मे पधारें और हमें सेवा का सौभाग्य दें। चोर ने सोचा बचने का यही अवसर है. वह राजकीय अतिथि बनने को तैयार हो गया. सब लोग जयघोष करते हुए नगर में ले जा कर उसकी सेवा सत्कार करने लगे। लोगों का प्रेम और श्रद्धा भाव देखकर ढोंगी का मन परिवर्तित हुआ. उसे आभास हुआ कि यदि नकली में इतना मान-सम्मान है तो सही में संत होने पर कितना सम्मान होगा. उसका मन पूरी तरह परिवर्तित हो गया और वह चोरी त्यागकर संन्यासी हो गया।

नया साल सिर्फ.जश्न नहीं, आत्म-परीक्षण और सुधार का अवसर भी

एक नया साल एक नई शुरूआत है। यह एक नए जन्म की तरह है। नया साल शुरू होते ही हमें लगता है कि हमें अपने जीवन में बदलाव करने, नई राह पर चलने, नए काम करने और पुरानी आदतों, समस्याओं और कठिनाइयों को अलविदा कहने की जरूरत है। अक्सर हम नई योजनाएँ और नए संकल्प बनाने लगते हैं। हम उत्साहित, प्रेरित और आशावान महसूस कर सकते हैं, लेकिन कभी-कभी आशंकित भी होते हैं। कवियों और दार्शनिकों ने अक्सर दोहराया है कि भविष्य में जो कुछ भी करना है, उसमें जीवन ने जो सबक हमें सिखाया है, उसे लागू करना जरूरी है। लेकिन यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। लोग एक-दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएँ देते हैं। संदेश, ग्रीटिंग कार्ड और उपहारों का आदान-प्रदान नए साल के जश्न का अभिन्न अंग है। मीडिया कई नए साल के कार्यक्रमों को कवर करता है, जिन्हें दिन के अधिकांश समय प्राइम चैनलों पर दिखाया जाता है। जो लोग घर के अंदर रहने का फैसला करते हैं, वे मनोरंजन और मौज-मस्ती के लिए इन नए साल के शो का सहारा लेते हैं। नया साल सिर्फ.जश्न मनाने का समय नहीं है, बल्कि आत्म-परीक्षण और सुधार का अवसर भी है। अतीत की गलतियों से सीखते हुए हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। आइए हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें और उन्हें प्राप्त करने की योजना बनाएँ। आइए हम नकारात्मकता को पीछे छोड़ें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएँ। आइए हम जरूरतमंदों की मदद करके समाज के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी निभाएँ। आइए हम आत्म-विकास के लिए प्रयास करते रहें और नई चीजें सीखते रहें। लोग रंग-बिरंगे कपड़े पहनते हैं और मौज-मस्ती से भरी गतिविधियाँ करते हैं जैसे गाना, खेलना, नाचना और पार्टियों में जाना। नाइट क्लब, मूवी थिएटर, रिसॉर्ट, रेस्टोरेंट और मनोरंजन पार्क हर उम्र के लोगों से भरे हुए हैं। आने वाले साल के लिए नए संकल्पों की योजना बनाने की सदियों पुरानी परंपरा आम है। कुछ सबसे लोकप्रिय संकल्पों में वजन कम करना, अच्छी आदतें विकसित करना और कड़ी मेहनत करना शामिल है। आज के समय में, जब पर्यावरण के मुद्दे एक गंभीर चिंता का विषय हैं, तो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील तरीकों से नए साल का जश्न मनाना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। पटाखों का उपयोग कम करना, पेड़ लगाना और जल संरक्षण इस दिशा में सकारात्मक कदम हो सकते हैं।

नया साल हमें अतीत की कड़वाहट को भूलकर नए रिश्ते शुरू करना सिखाता है। आइए हम एक-दूसरे के प्रति प्रेम और सद्भावना व्यक्त करें। आइए हम उन लोगों को सही रास्ते पर लाने का प्रयास करें जो अपना रास्ता भूल गए हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण की शिक्षाएँ हमें याद दिलाती हैं कि हमें अपना काम करना चाहिए और परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। नया साल सिर्फ.कैलेंडर बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को एक नई दिशा देने का अवसर है। यह नई ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का समय है। आइए हम सब मिलकर इस नए साल को अपने और समाज के लिए बदलाव का साल बनाएँ। अब, सभी चमक-दमक के बीच, नए साल का दिन कुछ गंभीर सोच-विचार का भी समय है। हाँ, हम आत्मनिरीक्षण के बारे में बात कर रहे हैं-पिछले साल को पीछे देखते हुए और यह पता लगाते हुए कि हमने क्या सीखा है। क्या हमने आखिरकार मकड़ियों के डर पर विजय प्राप्त की? क्या हमने उन लोगों के साथ पर्याप्त समय बिताया जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं? यह कुछ हद तक हमारे जीवन की मुख्य घटनाओं को स्क्रॉल करने और यह सोचने जैसा है, ₹वाह, क्या मैंने वाकई ऐसा किया?₹ एक पेड़ लगाएँ, अपने भविष्य के लिए एक पत्र लिखें, या बोर्ड गेम का लुत्फ उठाएँ। इसे अपने लिए अनोखा बनाएँ और हर साल इसका इंतजार करें। अब, इस तरह से आप एक परंपरा की शुरूआत कर सकते हैं! नए साल के दिन सोच-समझकर उपहार देकर प्यार फैलाएँ। यह क़ीमत के बारे में नहीं बल्कि इशारे के पीछे की भावना के बारे में है। एक हस्तलिखित नोट, एक व्यक्तिगत ट्रिंकेट, या एक हार्दिक संदेश दुनिया भर में अंतर ला सकता है जब आप उन लोगों के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अक्सर, हम या तो इसे महसूस नहीं करते या इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं और एक ऐसी कहानी लिखने की कोशिश करते हैं जो पहले ही खत्म हो चुकी है। ऐसे समय में हमें याद रखना चाहिए कि कभी-कभी कलम को नीचे रखना ठीक होता है। बंद दरवाजे से जूझना ठीक नहीं है। इससे चिपके रहने से आप दूसरी तरफ की खिड़की को देख नहीं पाते। जैसा कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिशनर कहते हैं, सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि नए सिरे से शुरूआत करने के लिए आपके पास मौजूद पल से बेहतर कोई समय नहीं है। नए साल की सुबह, सबसे अच्छी स्थिति में, केवल सही सेटिंग ही बना सकती है; बाकी, जैसा कि वे कहते हैं, सब आपके भीतर है। हालाँकि, आप नए साल के दिन 2025 को धूम मचाने का फैसला करते हैं, इसे यादगार बनाते हैं। ऐसे नाचें जैसे कोई देख नहीं रहा हो, ऐसे हँसें जैसे यह अब तक का सबसे अच्छा मजाक हो और अपने दोस्तों को ऐसे गले लगाएँ जैसे आपने उन्हें एक दशक से नहीं देखा हो। क्योंकि अंदाजा लगाइए क्या? 2025 आपका चमकने का साल है।

प्रियंका सौरभ

मणिपुर प्रकरण : जातीय हिंसा का समाधान संवाद से संभव

मणिपुर में जातीय संघर्ष, व्यापक हिंसा एवं अराजक माहौल के लिए पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बीते साल के आखिरी दिन शांति की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए माफी मांगी है, इस माफी को लेकर राजनीति के गलियारों में व्यापक चर्चा है। क्योंकि इस हिंसा में मई 2023 से 250 से अधिक लोगों की जान चली गई और हजारों लोग बेघर हो गए है। लम्बे समय से यह प्रांत अस्थिरता, असंतोष एवं अशांति की आग में जल रहा है। एन बीरेन सिंह ने माफी मांगते हुए हिंसा के इस लंबे कालखण्ड एवं सिलसिले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और सभी समुदायों से अपील की कि पिछली गलतियों को भुलाकर वे शांति और सौहार्द कायम करें। हालांकि मुख्यमंत्री की इस अपील के अपने मतलब निकाले जा रहे है। कुछ लोगों का कहना है कि यह माफी बहुत पहले मांगी जानी चाहिए थी। कुछ का यह मानना है कि माफी ऐसे समय आई है जब मुख्यमंत्री चौतरफा दबाव में है। विरोधी तो बहुत पहले से उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, पिछले कुछ समय से खुद उनके विधायकों और सहयोगियों ने इस माफी को उनकी मजबूरी का परिणाम बताया है। निश्चित ही बीरेन सिंह के लिये माफी मांगना काफी नहीं है, अगर वह मानते हैं कि स्थिति को संभालने में नाकाम रहे तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था या केन्द्र को राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए था। अफसोसनाक यह है कि इस मसले पर अक्सर विवाद उभरते रहे और राजनीतिक शख्सियतों के बीच आरोप-प्रत्यारोप अक्सर बेलगाम बोल में तब्दील ही होते रहे, कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया, जो गैरजिम्मेदाराना राजनीति को दर्शाता है।

मणिपुर में 3 मई 2023 से ही बहुसंख्यक मैतेई और कुकी के बीच आरक्षण और आर्थिक लाभ को लेकर जो हिंसा शुरू हुई वह अभी थमने का नाम नहीं ले रही। कभी अपनी सांस्कृतिक सद्भावना के लिए जाना जाने वाला राज्य अब गहराते विभाजन एवं जातीय संघर्ष का सामना कर रहा है और लोग लगातार भय में जी रहे हैं। तनाव कम होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा। शांति एवं सद्भावना की तलाश अभी भी जारी है। मणिपुर में जब चंद दरिंदें दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनके साथ बर्बरतापूर्ण हरकत करते नजर आए तो पूरा प्रांत आक्रोश में आ गया। जनमानस की प्रतिक्रिया लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत महत्व रखती है। न तो राज्य सरकार ने और न ही केन्द्र सरकार ने हिंसा को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय किए और न ही शांति स्थापित करने के कोई प्रयास किए गए। मुख्यमंत्री एन. बीरेन सरकार डेढ़ साल से ज्यादा समय से खेमों में बंटती राजनीतिक उलझन में फंसी रही। सभी दल, नेता एवं सरकार नामुमकिन निशानों की ओर कौमों को दौड़ती रही। यह कौमों के साथ नाइंसाफी होने के साथ अमानवीयता की चरम पराकाष्ठा थी। क्योंकि ऐसी दौड़ जहां पहुंचाती है, वहां कामयाबी की मंजिल नहीं, बल्कि मायूसी का गहरा गड्ढा होता है।

मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह स्वीकारोक्ति कि ह्यमैं राज्य में जो कुछ हुआ उसके लिए खेद व्यक्त करना चाहता हूं। कई लोगों ने अपनों को खो दिया और कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा।

मैं खेद व्यक्त करता हूं और माफी मांगता हूं। लेकिन पिछले तीन-चार महीनों में अपेक्षाकृत शांति देखने के बाद, मुझे उम्मीद है कि आने वाले साल में स्थिति सामान्य हो जाएगी। प्रश्न है कि मुख्यमंत्री 18 माह के खून-खराबे के बाद अब क्यों माफी मांग रहे हैं? वे क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर वह स्थिति को संभालने में नाकाम रहे थे तो उन्हें बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। ताकि स्थितियों लगातार इतनी विकराल नहीं होती, इतनी अधिक जनहानि नहीं होती। देश के नेताओं को गाल बजाने की बजाय आम आदमी को परेशान करने वाली सामाजिक असुरक्षा, जातीय संघर्ष तथा हिंसा जैसे मुद्दों से निबटने के लिये दूरगामी नीतियों के क्रियान्वयन के प्रयास करने चाहिए। यूं तो मणिपुर हिंसा में इतने मासूमों की मौत के बाद मुख्यमंत्री के माफी मांगने का कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा। इसीलिये विपक्ष दल एवं कांग्रेस उन पर और केन्द्र सरकार पर हमलावर है। 19 महीनों में एन.बीरेन असंवेदनशील बने रहे और वर्ष के अंत में उन्होंने माफी मांगकर किस संवेदनशीलता का परिचय दिया है? अब सवाल यह है कि त्रासदी का अंत कैसे हो? कैसे शांति स्थापित हो? जरूरत है मनुष्य को बांटे नहीं, सत्य को ढंके नहीं।

बड़ा सवाल यह है कि राज्य द्वारा माफी मांगना केवल दिखावा है और राजनीतिक अपयश निवारण और क्षतिपूर्ति की आवश्यकता मात्र है या किसी सार्थक बदलाव की बुनियाद। हालांकि इस तरह की राजनीतिक माफी अक्सर संदेहास्पद ही होती है क्योंकि माफी में इससे कहीं अधिक की क्षमता होती है। सार्वजनिक रूप से माफी मांगने वाले नेताओं की संख्या में वृद्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय एवं चिन्तनीय रही है। माफी मांगना एक ऐसी युक्ति है जिसका इस्तेमाल नेता अब अक्सर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिये करते हैं, ताकि वे कम से कम लागत पर अपनी गलतियों को पीछे छोड़ सकें या उनसे पीछा छूडा सके। लेकिन बीरेन सिंह की माफी की अच्छी बात यह है कि तमाम दबावों के बाद ही सही, राजनीति और समाज के हर प्रमुख हिस्से ने उनकी माफी को सकारात्मक कदम माना है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इस माफी की पहल को विश्वसनीय बनाया जाये एवं ऐसे उपयोगी एवं जरूरी कदम उठाए जाये ताकि मणिपुर राज्य में मैतेई समुदाय और पहाड़ी क्षेत्रों में कुकी जनजातीय समुदायों के बीच चला आ रहा टकराव विराम पा जाये। जरूरी है कि केंद्र और राज्य की सरकार मुख्यमंत्री की इस पहल से उपजे सद्भाव को स्थायित्व देने की कोशिशें अविलंब शुरू कर दें।

2023 के मुकाबले 2024 की दूसरी छमाही में मणिपुर के हालात बेहतर रहे, संघर्ष की स्थितियां कम देखने को मिली। लेकिन पूर्व की हिंसक घटनाओं और मृतकों की संख्या को उससे बनने वाले माहौल से अलग करके नहीं देखा जा सकता। तनाव, संघर्ष और अविश्वास के जिस माहौल से मणिपुर गुजर रहा है, उसकी सचाई इसी हफ्ते कांगपोकपी जिले में कथित कम्युनिटी बंकरों को सुरक्षा बलों द्वारा नष्ट किए जाने पर हुए संघर्ष में 40 लोगों के जख्मी होने और कुकी नैशनल फ्रंट के कथित हमलों के खिलाफ चुराचांदपुर जिले में बंद का आह्वान किए जाने से स्पष्ट है। अभी भी असामान्य हालातों के बीच सवाल है कि मुख्यमंत्री की इस माफी का राज्य के अलग-अलग समुदायों के लोगों पर कैसा और कितना असर पड़ेगा? सवाल महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यह आरोप संघर्ष शुरू होने के बाद से ही लगता रहा है कि मुख्यमंत्री और राज्य प्रशासन की भूमिका निरपेक्ष नहीं है। आरोप पूरी तरह गलत हो तो भी इससे इतना तो स्पष्ट है कि प्रदेश के लोगों का एक खेमा उन्हें अविश्वास भरी नजरों से देखता है। इतने गंभीर और मानवता के अस्तित्व को ही नकारने से जुड़े मसले पर भी समाज के लोगों में जो बंटवारे की प्रवृत्ति राजनीतिक कारणों से दिख रही है वो किसी भी नजरिए से देश की एकता और अखण्डता के लिये फायदेमंद नहीं है। मुद्दा चाहे कोई भी, खांचों या खेमों में बांटने या बंटने का और आम लोगों को तोड़ने का या जोड़ने का-राजनीति से जुड़े लोगों, राजनीतिक दलों और नेताओं में तो शुरू से रहा है लेकिन जब समाज में आम लोग भी इस तरह के बंटवारे का हिस्सा बन जाते हैं तो इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ देश के नागरिकों का होता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सरकार संकट में सही ढंग से नहीं निपटने के चलते अपनी विश्वसनीयता पहले ही खो चुकी है, लेकिन उसे पुनः हासिल करने के लिये माफी से आगे बढ़कर और अधिक सामाजिक एकता, समरसता एवं सौहार्द के प्रयत्न करने होंगे। हमारे देश की राजनीति की विडम्बना ही रही है कि लोगों को धर्म, जाति, वर्ग, भाषा, वर्ण के नाम पर बांट कर किसी न किसी तरह सत्ता हासिल करना। हालांकि सही मायने में लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति की परिभाषा और दायरा उससे कहीं ज्यादा व्यापक है। जातीय हिंसा का समाधान संवाद से ही होता है। राज्य सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मैतेई और कुकी समुदाय के साथ लगातार संवाद जारी रखना चाहिए।

जो डिटेंशन पालिसी : एक बड़ा कदम

नो डिटेंशन पालिसी से अधिकतर बच्चे पढ़ाई में मेहनत नहीं करते थे और आगे नौवीं और दसवीं कक्षा में जाने पर उनको परेशानी का सामना करना पड़ता था। कहीं न कहीं अभिभावक भी बच्चों की पढ़ाई पर थोड़ा कम ध्यान देते थे, क्यों कि उनको यह रहता था कि बच्चा नहीं पढ़ेगा, तब भी स्कूल को पास तो करना ही है। नो डिटेंशन पालिसी की वजह से कहीं-कहीं उनके मन में यह बात जरूर रहती थी कि जब सरकार का नियम हो है कि बच्चों को आठवी तक पास करना ही है तो फिर ज्यादा चिंता करने की क्या जरूरत है। अब, नो डिटेंशन समाप्त होने से बच्चों और अभिभावकों दोनों की पढ़ाई के प्रति गंभीरता बढ़ेगी। इसके अच्छे परिणाम आएंगे। पहले भी इसी तरह का नियम होता था। लेकिन बीच में नो डिटेंशन पालिसी के आने से पढ़ाई के प्रति बच्चों में गम्भीरता कम हो गई और नौवी और दसवीं में जाने पर उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ने लगा और इसी वजह से नौवीं और दसवी के रिजल्ट में भी गिरावट आने लगी। अभी तक यह होता था कि-चाहे बच्चा पांचवीं का है या छठी का है कोर्स खत्म कर पाया हो या नहीं, उसने पूरा सिलेबस पढ़ा हो या नहीं, उसको अगली कक्षा मे प्रमोट करता ही ही। इस तरह से बच्चे की बुनियाद कमजोर हो जाती थी। और आगे नौंवी कक्षा में जाने पर बच्चों के ऊपर पढ़ाई का एकदम बोझ पड़ जाता था और अधिकतर बच्चे फेल हो जाते थे। इस पालिसी के खत्म होने से अब बच्चों की पढ़ाई के स्तर में सुधार होगा और उनको पढ़ाई की जड़ भी मजबूत होगी। इस पालिसी को शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से शुरू किया गया था लेकिन उसे समाप्त करना हो यह दर्शाता है कि-टेस्ट का मौका दिया जायेगा। टेस्ट में पास होने पर उसको अगली कक्षा में प्रमोट किया जायेगा। इससे पढ़ाई पूरी कर के हो टैलेंटेड बच्चे आगे जाएंगे। हमारे समय में भी यही नियम था। परीक्षा पास करने के लिए एक बार हो चांस मिलता था। और उसमें यदि फेल हो जाते थे तो फिर उसी कक्षा में पढ़ाई करनी पड़ती थी। लेकिन बाद में यह नियम आने से कि बच्चा फेल हो तो भी उसे प्रमोट करना हो है, इस नियम से बच्चों के टेलेंट में कमी आने लगी। अब इस व्यवस्था के खत्म होने से आगे मेहनत कर के और मेहनत से हो कर के जो बच्चों आगे बढ़ेगा वह आगे भी जाकर अच्छा करेगा। उसका भविष्य भी उज्ज्वल होगा। उसे आगे अपने करियर मे तरक्की करने में किसी सिफारिश की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ देखें तो नो डिटेशन पॉलिसी को लाने की जरूरत क्यों पड़ी थी। यह राइट टू एजुकेशन एक्ट-2009 से जुड़ा है जिसकी धारा 16 में यह प्रावधान किया गया कि स्कूलों में आठवी क्लास तक किसी भी बच्चे को किसी भी क्लास की परीक्षा में फेल नहीं किया जायेगा। घोषित नहीं किया जायेगा।

न हीं उसका अगली क्लास में जाना रोका जा सकेगा। इसके पीछे यह सोच थी कि सभी बच्चों के लिए कम से कम आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई सुनिश्चित की जाए। देखा गया था कि-आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े परिवारों के बच्चों में फेल हो जाने की वजह से ड्रॉप आउट बढ़ जाता है। अक्सर कमजोर बच्चों के बारे में यह धारणा बन जाती है कि यह पढ़ने वाला बच्चा नहीं है। लिहाजा उन्हें दूसरे काम में लगाने का भाव परिवार में भी जोर पकड़ने लगता है और वे पढ़ाई से वंचित कर दिये जाते हैं। नो डिटेंशन पॉलिसी के पोछे यह सोच भी थी कि बच्चे का सतत मूल्यांकन किया जाये जिससे उसे पास-फेल घोषित करने के बजाय उसकी कमियों का पता लगाकर उनका निदान करने का काम निरंतरता के साथ होता रहे। यह माना गया था कि कच्ची उम्र में बच्चे की पात्रता देखने का खास मतलब नहीं, क्योंकि हर बच्चा सीख सकता है। सवाल उसे सिखाने की सही प्रक्रिया ढूंढ़ने और उसे अपनाने का है। जो मूलतः शिक्षा तंत्र की जिम्मेदारी है। नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने का एक मजबूत कारण यह बना कि इस पॉलिसी को लागू किये जाने के बाद फीडबैक पॉजिटिव नहीं आया। यह शिकायत आम थी कि बच्चों और अभिभावकों में पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी कम होती जा रही है। कई राज्यों की ओर से इस पॉलिसी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग हो रही है। इन्हीं वजहों से 2019 में केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार (राइट टु एजुकेशन (आरटीई) कानून में संशोधन किया, जिससे संबंधित सरकारों को इसे जारी होने या छोड़ देने का विकल्प मिला और अब केंद्र सरकार ने भी इसे छोड़ने का विकल्प चुना। गौर तलब है कि अब भी पचास फीसदी राज्यों में नो डिटेंशन पालिसी लागू है और तमिलनाडु में केंद्र के फैसले के बाद भी खुलकर कहा है कि पॉलिसी को जारी रखा जाएगा।

> अब भी पचास फीसदी राज्यों में नो डिटेंशन पालिसी लागू है और तमिलनाडु में केंद्र के फैसले के बाद भी खुलकर कहा है कि पॉलिसी को जारी रखा जाएगा।

चेक बाउंस के ही 45 लाख से अधिक मामलें न्यायालयों में विचाराधीन

केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि देश के न्यायालयों में 45 लाख से अधिक मामलें केवल और केवल चेक बाउंस होने से संबंधित है। अदालतों में लंबित मुकदमों में करीब 9 प्रतिशत मामलें तो चेक बाउंस के ही है। इसमें भी सर्वाधिक 6 लाख से अधिक मामले राजस्थान में विचाराधीन है वहीं राजस्थान के साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य है जहां चेक बाउंस के सर्वाधिक मामले विचाराधीन है। न्यायालयों में मुकदमों के बोझ को लेकर न्यायपालिका से लेकर सरकार और इससे जुड़े लोग सभी चिंतित है। देश के न्यायालयों में कुल 5 करोड़ से अधिक मामलें लंबित चल रहे हैं। लगातार सुधारों और सकारात्मक प्रयासों के बावजूद न्याय की प्रतीक्षा में इतनी अधिक संख्या में प्रकरणों का बकाया होना इस मायने में भी चिंता का कारण है कि न्यायालयों पर मुकदमें को बोझ कम होने के स्थान पर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यह सब तो तब है जब लोक अदालतों का समय समय पर लगातार आयोजन किया जा रहा है। दरअसल कुछ इस तरह के मुकदमें है जो सबसे अधिक न्याय के मंदिर का बोझ बढ़ा रहे हैं। ऐसे मुकदमों के निस्तारण की दृष्टि से यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले मुकदमों के निस्तारण का जो रास्ता अख्तियार किया गया है वह निश्चित रुप से सराहनीय और न्यायालयों के बोझ को कम करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास माना जा सकता है। यदि चेक बांउस वाले मामलों को भी इसी तरह से निपटान का कोई रास्ता निकल सके तो न्यायालयों में मुकदमों के अंबार को निश्चित रुप से कम किया जा सकता है।

न्यायपालिका और सरकार न्यायालयों में मुकदमों के अंबार से चिंतित होने के साथ ही समाधान की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। चेक बांउस जैसे मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए सुझाव देने के लिए 10 मार्च, 21 को दस सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई समिति ने नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंटल कोर्ट बनाने की सलाह के साथ ही पायलट प्रोजेक्ट के रुप में स्थापना के सुझाव भी दिए और पायलट प्रोजेक्ट के रुप में करीब25 कोर्ट बने भी। पर परिणाम सामने नहीं आ सके हैं।

अदालतों में लंबित मुकदमों के अंबार को इसी से समझा जा सकता है कि देश में 5 करोड़ से अधिक मुकदमों में वादी प्रतिवादी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि इनमें से एक लाख 80 हजार मामलें तो 30 साल से भी अधिक समय से लंबित चल रहे हैं। देश के सबसे बड़े न्याय के मंदिर में 80 हजार से अधिक मामलें लंबित है। एक मोटे अनुमान

के अनुसार लंबित न्यायालयों में से करीब 85 प्रतिशत से अधिक मामलें तो जिला अदालतों में विचाराधीन है। करीब 25 प्रतिशत मामलें राजस्व से जुड़े हैं। यातायात नियमों की अवहेलना के मामलें भी बहुत अधिक संख्या में है पर इसके निराकरण का रास्ता निकलने लगा है। देश में समय समय पर नियतकाल में लग रही लोक अदालतों में भी बड़ी संख्या में मुकदमों का निस्तारण होने लगा है। पर सवाल वहीं का वहीं हैं कि देष के न्यायालयों में फास्ट ट्रेक सहित विशेष अदालतें बनने के बाद भी कम होने की जगह दिन प्रतिदिन अधिक ही होते जा रहे है। विचाराधीन कैदियों के संदर्भ में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु की टिप्पणी और उपकी चिंता से सभी वाकिफ हो चुके हैं। होता तो यहां तक है कि हजारों की संख्या में ऐसे प्रकरण देखने को मिल जाएंगे जिसमें जितनी सजा होनी चाहिए उससे अधिक समय तो ज्यूडिशियल कस्टेडी में ही निकल जाता है। इसी तरह से मामूली मारपीट और इसी तरह के दूसर छोटे मोटे मुकदमें न्यायालयों में लगातार बोझ का कारण बनते जा रहे हैं। आपसी जमीन जायदाद और गज दो गज जमीन के, रास्ते के और इनके कारण राजस्व मुकदमों के साथ ही क्रिमिनल मुकदमों और इसी तरह के मुकदमों के न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करते हुए त्वरित निस्तारण का कोई समाधान खोजा जाना आवश्यक है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे न्यायालयों द्वारा मुकदमों का बोझ कम करने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। व्यवस्था में काफी सुधार किये गए हैं। पुराने लंबित मुकदमों की पहले सुनवाई पर जोर दिया जा रहा है। इसी तरह से तारीख पर तारीख लेने की परंपरा को भी तोड़ा जा रहा है। व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और तकनीक सेवी बनाया जा रहा है। त्वरित निस्तारण पर जोर दिया जा रहा है। पर तथ्य तो यही दर्शा रहे हैं कि लाख प्रयासों के बावजूद मुकदमों का अंबार कम नहीं हो रहा। भारतीय न्याय प्रणाली को लेकर सबसे सकारात्मक पक्ष यह है कि देशवासियों को न्याय सिस्टम के प्रति विष्वास है और यही कारण है कि लोग जब कोई विकल्प नहीं दिखता तो न्याय के दरवाजे पर गुहार लगाते है।

तस्वीर का एक पहलू यह भी है कि न्यायालयों में सरकार से जुड़े मुकदमों की संख्या भी बहुत बहुत बड़ी संख्या में हैं। आर्बिटेशन के प्रावधान होने के बावजूद अधिक मामलें निपट नहीं पाते हैं। अब चेक बांउस के मामलों को ही लिया जाए तो इसमें दो बाते साफ है। मोटे रुप से चेक बांउस होने की स्थिति में 2 वर्ष की सजा या चेक राशि की दो गुणा राशि चुकाने के प्रावधान है। केस की प्रकृति के अनुसार सजा कम ज्यादा हो सकती है। ऐसे में 43 लाख मुकदमों का केवल चेक बाउंस से संबंधित होना इसलिए चिंता का विषय हो जाता है कि पांच करोड़ में से यह संख्या कम होती है और खासतौर से ऐसे हालातों में निचली अदालत में मुकदमों का बोझ काफी कुछ कम हो सकता है। इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता तो चेक बांउस प्रकरणों के निपटान के लिए विशेष अभियान चलाते हुए लोक अदालत लगाई जाकर उसमें दोनों पक्षों को बुलाकर समझाईश से निपटाया जा सकता है या कुछ इसी तरह का कोई हल खोजा जा सकता है। ऐसे मामलों में एक या दो से अधिक तारीख तो दी ही नहीं जानी चाहिए। ऐसे मामलें अदालत में आने की साथ ही दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का तारीख दर तारीख नहीं बल्कि पहली या दूसरी तारीख में ही देकर के निस्तारित किया जाना अधिक उचित होगा ताकि इस तरह के प्रकरणों का निष्पादन हो सके। यह तो सामान्य व्यक्ति के रुप में सुझाव हो सकता है। न्यायपालिका से जुड़े विशेषज्ञ विद्वतगण इस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए न्यायिक प्रक्रिया को पूरी करते हुए कोई सकारात्मक सुझाव दे और सरकार व न्यायपालिका द्वारा परीक्षण कर कोई ऐसी व्यवस्था करें तो मुकदमों के अंबार को कम किया जा सकता है। चेक बांउस तो एक पक्ष है इसी तरह के ऐसे मुकदमें जिनमें अधिक कानूनी पेचिदगियां नहीं होती हो उनके त्वरित निस्तारण का रास्ता निकाल कर न्यायालयों के बोझ को हल्का किया जा सकता हैं। सरकार, न्यायपालिका और इस क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों को इस दिशा में भी निरंतर मनन और समाधान खोजना ही होगा ताकि न्याय जल्दी मिल सके, मुकदमों का भार कम हो सके। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

नया टर्मिनल निर्माण की मिली अनुमति, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का इंवायरमेंटल क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी

वर्जन-प्रदूषण बोर्ड के साथ मिलकर जन सुनवाई का आयोजन किया गया था। इस दौरान एयरपोर्ट के आस-पास से आए लोगों ने भी अपने सुझाव दिए थे। इसमें किसी की तरफ से कोई आपत्ति नहीं आई थी। इस आधार पर प्रदूषण बोर्ड से इंवायरमेंटल क्लीयरेंस सर्टिफिकेट मिल गया है। बहुत जल्द नए टर्मिनल का निर्माण शुरू हो जाएगा।

आरके पराशर,
एयरपोर्ट निदेशक

गोरखपुर। कुनराघाट में वायुसेना स्टेशन के अंदर नया टर्मिनल बनने का रास्ता साफ हो गया। गत दिनों शुक्रवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्माण के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। बीते दिनों जन सुनवाई में आम जनता से आपत्ति और सुझाव लिए गए थे। किसी ने भी आपत्ति नहीं दर्ज कराई थी। इस आधार पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इंवायरमेंटल क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी कर दिया है।

पिछले दिनों रक्षा मंत्रालय ने गोरखपुर एयरपोर्ट के लिए 42.14 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की अनुमति दी थी। प्रस्ताव में ए-320 प्रकार के विमानों के संचालन के लिए नया सिविल एन्क्लेव, बेसमेंट सहित 62 हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल वाला नया टर्मिनल भवन, इससे जुड़ने वाले वॉकवे के साथ ही बेसमेंट और बहु स्तरीय कार पार्किंग, 3.5 मीटर शोल्डर के साथ 23 मीटर चौड़ाई के दो लिंक्ड टैक्सी-वे शामिल है। करीब 28 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में 900 कारों और टर्मिनल भवन के बेसमेंट पार्किंग में तीन सौ गाड़ियों को पार्क करने की व्यवस्था की जाएगी। 11 सौ 72 करोड़ रुपये से नया टर्मिनल बनाया जाएगा। डीपीआर भी तैयार हो गया है।

एयरपोर्ट विस्तार के बाद यहां एक बार में 10 जहाज को खड़े हो सकेंगे। अभी वर्तमान में एक बड़ा और छोटा हवाई जहाज पार्क हो पाता है। इसका विस्तार तीन तरफ से किया जाएगा, जिससे यहां एक साथ 1500 यात्री चेकइन या चेक-आउट कर सकें। नए एयरपोर्ट पर दिल्ली एयरपोर्ट की तर्ज पर पांच ऐरो ब्रिज बनाए जाएंगे। इस ब्रिज से यात्री सीधे चेकइन लाउंज से विमान में सवार हो सकेंगे। यात्रियों को रनवे पर पैदल जाने की जरूरत नहीं होगी। नए टर्मिनल के बनने के बाद विमान की संख्या बढ़ सकती है। जम्मू, गोवा समेत अन्य शहरों के लिए भी हवाई सेवा शुरू हो सकती है।

अलाव

आग केवल जलाती नहीं रिश्ते जोड़ती है। शीत ऋतु की आग में जीवन होता, भाईचारा होता। शीत की गहराई मशीन नहीं प्रकृति बताती। सेंटीग्रेड नहीं था पर ठिठुरते पशु पक्षी ताप बता देते। बूढे बरगद को सब याद रहता। किसी का जन्म, किसी की मृत्यु तय करती, किस वर्ष शीत लहरी कितने दिन चली।

शीत लहर आती लेकिन जिंदगी चलती रहती उसी शान से। यह शान थी आग। कौआबुलाने के समय ही अलाव जल जाते। धुएँ की चादर गाँव पर तन जाती। घने कुहरे से लड़ता धुआँ बस्ती का आकाश दीप था।

ये केवल अलाव नहीं थे गाँव के सभागार थे प्रेम और सौहार्द थे। वहाँ जाति धर्म नहीं था। कोई बड़ा छोटा नहीं। किसी कै अलाव पर कोई बैठता। आग सबको समा लेती। राह चलते राहगीर भी दो घड़ी आग ताप लेते और इस बहाने हाल खबर बता देते।

गाँव के समाचार पत्र थे अलाव। धूप निकलने तक जवार नहीं देश की खबरें मिल जाती। अलाव यूँ ही नहीं जलते थे उसकी भी प्रक्रिया थी। गांव के इर्दगिर्द फैले झाड़झंखाड़ ज्वार बाजरे की खेत में पड़ी गाँठे इस बहाने साफ हो जाते। आग ही नहीं पूरी प्रकृति शीत से लड़ने के लिए मनुष्य के साथ खड़ी हो जाती।

कुएँ का जल शीतलता का स्वभाव त्याग उष्ण हो जाता। नीम और बरगद स्वयं भीगते ठिठुरते टपटप आँसू टपकाते पर शीत की हिम्मत नहीं थी कि उनकी छाया को बेध कर नीचे बैठे चेतन प्राणियों को पीड़ित कर सके।

कौन कहता है प्रकृति जड है उन्हें सचेतन का पोषण आता है। यह चेतना किसने दी।

छाया से निर्धन, बेचारा बबूल जब कोई सहायता न कर पाता तो अपनी हरी डाल देकर आत्महुति कर रक्षक बन जाता। चिकनी पत्तियाँ और हरी डालें सूखी लकड़ियों से भी तेज जलती।

अलाव केवल अलाव नहीं दरवाजे की शोभा थे सभागार थे, ड्राइंग रूम थे, हैसियत थे। जिस-के अलाव पर जितनी भीड होती वह उतना ही प्रतिष्ठित। हर गांव मे कुछ अलाव मशहूर होते। ये अलाव गाँव की जिंदगी थे। हर टोले में एक बड़ा अलाव होता, छोटे तो घर घर होते।

महिलाओं का विमर्श अलग था। उपले पर आग लाने के बहाने बूढ़ी औरतें घरों का हाल ले जाती चूल्हे की आग भोजन बनाने मे रुचि पैदा करती। अकेले हीटर जलाये अखबार से शीत को नापते लोग अलाव का रस नहीं समझ सकते। आग गाँव का राग द्वेष प्रेम घृणा दुख सुख मित्रता शत्रुता सबका निर्णय करती। कौन किस अलाव पर बैठता है यह आग तय करती।

महिलाओं का विमर्श अलग था। उपले पर आग लाने के बहाने बूढ़ी औरतें घरों का हाल ले जाती चूल्हे की आग भोजन बनाने मे रुचि पैदा करती। अकेले हीटर जलाये अखबार से शीत को नापते लोग अलाव का रस नहीं समझ सकते। आग गाँव का राग द्वेष प्रेम घृणा दुख सुख मित्रता शत्रुता सबका निर्णय करती। कौन किस अलाव पर बैठता है यह आग तय करती।

अलाव साहित्य के नवरस अलाव में थे। क्या हुआ कपड़े नहीं हैं अलाव तो है और अलाव है तो युगों पुरानी कहानियां हैं परियों की राजाओं की और अपने अतीत की।

तब शीत आज की तरह मृत्यु की सूचक नहीं जीवन की सूचक थी। आदमी शीत मे प्रकृति के निकट हो जाता। कितनी दयालु है प्रकृति जीवन की रक्षा के लिए स्वभाव बदलना छोटी बात नहीं और एक हम हैं जिसकी जेब में आग कैद है हाथ में आग की बटन है पर यह आग केवल अपने लिए। हीटर सामने रखे बैठे हैं। यह मशीनी आग एकल होती है।

मनुष्य आज आग लगा रहा है जीवन में, समाज मे, अपनत्व में। मशीनों के बीच रहते रहते हम मशीन बन गये हैं। जेब मे आग है तो जलायेगी ही। अब तो सुनता हूँ गाँव मे भी अलाव नहीं जलते। वहाँ भी आग को कैद कर लिया गया है। शीत तब प्रेम की ऋतु थी यह प्रेम आग बाँटती थी। गाँव के बबूल अब शीत मे आत्महुति न देकर काँटे बाँटते होंगे, बूढा बरगद शीत में काँपता होगा और कुएँ सूख गये होंगे। प्रकृति से दूर होता मनुष्य मशीनों के बीच रहकर अब जीवन नहीं अखबारों में मृत्यु के आँकड़े गिन रहा है..!!

प्रफुल्ल सिंह 'रिक्त संवेदनाएं'
लखनऊ,
उत्तर प्रदेश

आखिर क्यों नहीं थम रहा रुपये में गिरावट का सिलसिला

निर्यात की तुलना में आयात में वृद्धि के कारण व्यापार घाटा बढ़ने से विदेशी मुद्रा का बहिर्वाह बढ़ता है, जिससे रुपया कमजोर होता है। कच्चे तेल और सोने के बढ़ते आयात के कारण 2022 में भारत का रिकॉर्ड व्यापार घाटा रुपये के मूल्यह्रास को बढ़ाता है। भारतीय रुपये में गिरावट बाहरी क्षेत्र की कमजोरियों के बीच मुद्रा स्थिरता बनाए रखने की चुनौतियों को रेखांकित करती है। मुद्रा मूल्य में उतार-चढ़ाव वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों जैसे रूस-यूक्रेन युद्ध, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और पूंजी बहिर्वाह के साथ-साथ राजकोषीय घाटे जैसे घरेलू कारकों से उत्पन्न होते हैं। भारत के बाहरी लचीलेपन को बढ़ाने और इसकी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए प्रभावी नीतिगत उपाय महत्त्वपूर्ण हैं।

सितंबर 2024 के शेयर शिखर के बाद निरंतर बहिर्वाह ने रुपये को कमजोर कर दिया क्योंकि निवेशक अमेरिकी ब्याज दरों में वृद्धि की अटकलों के बीच सुरक्षित परिसंपत्तियों की ओर चले गए। उच्च व्यापार घाटे जैसे व्यापार घाटे आयात पर बाहरी निर्भरता को उजागर करते हैं, विशेष रूप से ऊर्जा के लिए, रुपये की कमजोरी के दौरान चालू खाता घाटा बढ़ाते हैं। रुपये के अवमूल्यन के साथ भारत का कच्चे तेल का आयात बिल बढ़ गया, जिससे 2024 का व्यापार घाटा बढ़कर $75 बिलियन के करीब पहुँच गया। टैरिफ की धमकियाँ और ब्रिक्स मुद्रा विवाद जैसी वैश्विक घटनाएँ भारत के बाहरी व्यापार और निवेश के लिए अनिश्चितताएँ पैदा करके अस्थिरता को बढ़ाती हैं। ब्रिक्स देशों की मुद्रा योजनाओं के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति की 2024 टैरिफ चेतावनी ने बाजार में बिकवाली को बढ़ावा दिया, जिससे भारत की बाहरी स्थिरता कमजोर हुई। रुपये को स्थिर करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी निर्भरता निरंतर वैश्विक बाजार अशांति के दौरान दीर्घकालिक मौद्रिक लचीलेपन को प्रतिबंधित करती है।

रुपये को वापस 85.53 पर लाने के लिए दिसम्बर 2024 में एक ही तिमाही में $20 बिलियन से अधिक के भंडार को समाप्त कर दिया। कमजोर रुपया घरेलू मौद्रिक नीतियों को प्रतिबंधित करता है, महंगे आयातों के माध्यम से मुद्रास्फीति को बढ़ाता है जबकि विकास सम्बंधी चिंताओं को दूर करने के लिए राजकोषीय स्थान को कम करता है। दिसम्बर 2024 में कच्चे तेल के आयात की लागत 15% बढ़ गई, जिससे नीति निमार्ताओं पर मुद्रा प्रबंधन और राजकोषीय विस्तार रणनीतियों को प्रभावी ढंग से संतुलित करने का दबाव पड़ा। टैरिफ या प्रतिबंध जैसे संरक्षणवादी व्यापार उपाय, व्यापार संतुलन को बाधित करके मुद्रा स्थिरता को कमजोर कर सकते हैं। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच राजनीतिक अस्थिरता या संघर्ष अस्थिरता पैदा करते हैं, जिससे सुरक्षित-पनाहगाह डॉलर की मांग बढ़ती है और उभरते बाजारों की मुद्राएँ कमजोर होती हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया, जिससे भारत के आयात बिल पर दबाव पड़ा और रुपये का मूल्य कम हुआ। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में सख्त मौद्रिक नीतियों के कारण भारत से पूंजी का बहिर्वाह होता है, जिससे रुपये पर दबाव पड़ता है। 2022-23 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की दरों में बढ़ोतरी के कारण विदेशी पोर्टफोलियो का बहिर्वाह हुआ, जिससे रुपया कमजोर हुआ।

निर्यात की तुलना में आयात में वृद्धि के कारण व्यापार घाटा बढ़ने से विदेशी मुद्रा का बहिर्वाह बढ़ता है, जिससे रुपया कमजोर होता है। कच्चे तेल और सोने के बढ़ते आयात के कारण 2022 में भारत का रिकॉर्ड व्यापार घाटा रुपये के मूल्यह्रास को बढ़ाता है। उच्च घरेलू मुद्रास्फीति मुद्रा मूल्य को कम करती है, जिससे निर्यात कम प्रतिस्पर्धी हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है। कच्चे तेल जैसे अलोचदार आयातों की बढ़ती कीमतों ने भारत के आयात बिलों को बढ़ा दिया, जिससे 2023 में रुपया कमजोर हो गया। घरेलू और विदेशी निवेश में गिरावट कमजोर आर्थिक विक-ास का संकेत देती है, जिससे मुद्रा प्रवाह हतोत्साहित होता है। 2024 में, कॉर्पोरेट प्रदर्शन में कमी और स्टॉक वैल्यूएशन में वृद्धि के कारण विदेशी पोर्टफोलियो निवेश बहिर्वाह हुआ। मुद्रा को स्थिर करने के लिए केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप विदेशी मुद्रा भंडार द्वारा सीमित हैं और केवल अस्थायी राहत प्रदान कर सकते हैं। दिसम्बर 2024 में आरबीआई के देर से हस्तक्षेप ने रुपये को अस्थायी रूप से 85.53 प्रति डॉलर पर स्थिर करने में कामयाबी हासिल की। राजकोषीय रूप से विवश सरकार बाहरी झटकों को प्रबंधित करने की अपनी क्षमता को कम करती है, जिससे मुद्रा स्थिरता में विश्वास कमजोर होता है। महामारी के दौरान भारत के रिकॉर्ड राजकोषीय घाटे ने बाहरी लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी उपायों को सीमित कर दिया। मुद्रा नीतियों पर सरकार का स्पष्ट रुख निवेशकों का विश्वास बढ़ाता है और सट्टा दबाव कम करता है। आरबीआई गवर्नर द्वारा 2024 में डी-डॉलराइजेशन को खारिज करने से बाजार आश्वस्त हुआ, जिससे रुपये के मूल्यह्रास की चिंताएँ अस्थायी रूप से कम हो गईं। । बाह्य लचीलेपन को मजबूत करने के उपाय हैं, निर्यात को बढ़ावा देना और विदेशी मुद्रा आय बढ़ाने और व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए मूल्यवर्धित विनिर्माण और स-ेवाओं पर ध्यान केंद्रित करना। फार्मास्यूटिकल्स और आईटी जैसे क्षेत्रों को मजबूत करने से व्यापार घाटे को कम करने और रुपये को स्थिर करने में मदद मिल सकती है। विविध आपूर्तिकताओं के साथ दीर्घकालिक समझौते करके अस्थिर कच्चे तेल और आवश्यक आयात पर निर्भरता कम करें। रूस और मध्य पूर्वी देशों से कच्चे तेल के आयात का विस्तार करने से 2023 में औसत तेल आयात लागत कम हो गई। प्रभावी मुद्रा स्थिरीकरण के लिए सॉवरेन वेल्थ फंड और सोने के संचय के माध्यम से मजबूत भंडार बनाएँ। रिजर्व बैंक के अनुसार 2021 में $600 बिलियन के रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा भंडार ने महामारी के दौरान अस्थिरता को प्रबंधित करने में मदद की। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को निपटाने, अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने और विनिमय दर जोखिमों को कम करने के लिए समझौतों में शामिल हों। भारत-रूस रुपया-रूबल व्यापार तंत्र ने रूस-यूक्रेन संकट के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम किया। मुद्रा जोखिमों से बचने के लिए अल्पकालिक बाहरी ऋण को कम करते हुए कम लागत और लंबी अवधि के उधार को प्राथमिकता दें। भारत द्वारा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने में वृद्धि ने 2023 में पुनर्भुगतान अस्थिरता को कम करने के साथ स्थिर विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद की। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत के आर्थिक लचीलेपन के लिए एक मजबूत बाहरी क्षेत्र महत्त्वपूर्ण है। निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, विवेकपूर्ण राजकोषीय नीति सुनिश्चित करके, विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाकर और रुपये में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर, भारत मुद्रा अस्थिरता को कम कर सकता है। संरचनात्मक सुधारों और वैश्विक आर्थिक एकीकरण पर जोर देने वाली एक दूरदर्शी रणनीति दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करेगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को मजबूत करेगी।

- डॉ. सत्यवान सौरभ

बदलते माहौल में नेताओं को खुली चेतावनी

उधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने की प्रवृति पर चिंता जताई तो बदले में उन्हें अपने आसपास चिंता के स्वर सुनाई देने लगे । बहुत से संत-महंतों ने संघ प्रमुख से दो-टूक कह दिया कि वो पूरे हिंदू समाज का नेता बनने की कोशिश ना करें। हिंदू राजनीति में यह एक अलग तरह की हलचल है। सबसे पहली बात ये है कि अपने कर्म से इतर धर्म, नैतिकता, अहिंसा आदि पर बीच-बीच में प्रवचन देते रहना संघ के शीर्ष नेतृत्व की ऊँची सोच को दर्शाता है। अगर आप थोड़ी मेहनत करें तो एक ही सवाल पर मोहन भागवत के बयानों के कई परस्पर विरोधी वर्जन ढूंढ सकते हैं। ये बयान इसलिए दिये जाते हैं कि ताकि समय और राजनीतिक जरूरतों के मुताबिक ये दावा किया जा सके कि संघ ये चाहता है अथवा संघ ये नहीं चाहता है। मोहन भागवत ने ताजा बयान में कहा है कि हम लंबे समय से सद्भाव से रहते आये हैं और दुनिया को सद्भाव देना चाहते हैं तो हमें इसका एक मॉडल तैयार करना चाहिए। सुनने में ये बात अच्छी लग सकती है लेकिन सेक्यूलर इसे सिरे से हास्यास्पद कहेंगे । शांति-पूर्ण सह-अस्तित्व का मॉडल भारत में हजारों साल पुराना है और कामयाबी से चलता आया है। फिर भागवत जी कौन सा नया मॉडल तय करेंगे और क्यों ? मोहन भागवत की अगली बात महत्वपूर्ण हैं। सरसंघचालक ने कहा है कि राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग सोचते हैं कि नई जगहों पर ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदू नेता बन जाएंगे तो यह स्वीकार्य नहीं है। असली खबर इसी एक लाइन में छिपी है। इस लाइन का सीधा मतलब है कि आरएसएस कह रहा है कि धर्म की राजनीति के इकलौते कॉपीराइड होल्डर केवल कांग्रेस हैं। सवाल ये है कि आरएसएस को चुनौती कौन दे रहा है ? राहुल गाँधी लगातार कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई आरएसएस की विचारधारा से है। लेकिन भागवत जी की समस्या गाँधी नहीं बल्कि बढ़ता जातिवाद हैं। मोहन भागवत सद्भाव और सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था के शीर्ष पुरूष हैं और उन्ही के नक़्शे कदम पर चल नरेंद्र मोदी अब उनसे एक कदम आगे निकल चुके हैं। हिंदूत्व जागरूकता अब अपने आप में स्वयं हिंदू राष्ट्र हैं। चुनाव में मोदी लगभग हारते-हारते बचे और उसके बाद मोहन भागवत खुद को भगवान बताने वालों पर हमलावर हो गये। मोदी और भागवत का कट्टरता के विरोध में ये शीतयुद्ध आनेवाले दिनों में सिर्फ हिंदू राजनीति नहीं बल्कि समाज की दिशा भी तय करेगा। ये लड़ाई सनातन वर्चस्व और अति आक्रमक दोमुहे सेक्यूलर के बीच है। एक समय ब्राहण-बनिया पार्टी कही जानेवाली बीजेपी ने राम-मंदिर आंदोलन के समय बहुत बड़ी संख्या में पिछड़े समुदाय के लोगों को अपने साथ जोड़ा, नतीजे में देखते-देखते बीजेपी सत्ता के करीब पहुंच गई। लेकिन संघ के नेतृत्व ने बहुत होशियारी से सबकुछ अपने नियंत्रण में रखा। नब्बे के दशक में आया बीजेपी का तीव्र विस्तार कुछ समय के लिए थम गया। लगातार दो लोकसभा चुनावों में पार्टी को हार मिली। सबको को ये समझ में आने लगा कि बिखरे हुए बहुजन वोट का बड़ा हिस्सा हथियाये बिना ना तो सत्ता में वापसी और ना कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। ठीक ऐसे मौके पर नरेंद्र मोदी का उदय हुआ, उधर कांग्रेस के खाते में गुजरात दंगों के दौरान हिन्दुओं के विरोध से अर्जित किया गया धर्म विशेष सम्राट का टैग भी था। नरेंद्र मोदी के उदय के बाद सबकुछ बदल गया। किंग मेकर अब खुद मोदी का मोहताज हो गए । पहले ये कहा जाता था कि ब्राहण नेतृत्व अपनी हिंदू राजनीति के लिए पिछड़ों का होशियारी से इस्तेमाल कर रहा है। अब सवाल उलट चुका है, क्या उग्र हिंदुत्व की कमान अब मोदी के हाथ रहेगी और शीर्ष नेतृत्व पीछे-पीछे चुपचाप चलने को विवश होगा ? मोदी युग के आरंभ के बाद जो इको सिस्टम बना है, उसमें पिछड़ी जातियों से जुड़े लोग कई जगहों पर बहुत ताकतवर भूमिका में नजर आते हैं। आश्रम और मंदिर बनाने वाले बाबाओं की जो नई खेप आई है, उनमें बहुत बड़ी तादाद नरसिंहरानंद यति सरीखे पिछड़ों की है। मौजूदा राजनीति को ऐसे लोगों की सख्त जरूरत है लेकिन क्या आरएसएस इस बदलाव को सहजता से पचा पा रहा है? मुमकिन है, चित्तपावन संघ को उग्र होती हिंदू राजनीति की कमान अपने हाथ से छूटती दिखाई दे रही हो लेकिन उसके पास रास्ता है ! हिंसा और आक्रमकता को रोककर जिसने भी आतंकवाद को संरक्षण दिया है, आगे चलकर वो उसी का दमन करेंगे। भारत में मस्जिदों की खुदाई में मंदिर निकल रहे और आरएसएस इसमें राजनीति ढूंढ रहा है।

पंकज सीबी मिश्रा
जौनपुर यूपी

राष्ट्र सेवा में बाधक बनता सिविल सेवकों में बढ़ता तनाव

बढ़ते कार्यभार और सार्वजनिक अपेक्षाओं के कारण तनाव, थकान और घटती उत्पादकता सिविल सेवकों के बीच एक बढ़ती चिंता है। यह घटना शासन की दक्षता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है, जमीनी स्तर पर काम करने वाले सिविल सेवक सरकारी नीतियों की एक शृंखला के अंतिम कार्यान्वयनकर्ता और निष्पादक होते हैं और सामाजिक स्थिरता और सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए मूलभूत शक्ति होते हैं। वर्तमान में सिविल सेवाओं में तनाव का स्तर ऊँचा है क्योंकि कल्याणकारी राज्य की निरंतर बढ़ती अपेक्षाएँ, गठबंधन की राजनीति के कारण परस्पर विरोधी तथा कठिन दबाव, मीडिया का दबाव, सिविल सोसाइटी के आंदोलन इत्यादि सिविल सेवकों से ही तत्काल परिणाम चाहते हैं। इतनी जटिल परिस्थितियों में वही सिविल सेवक सफल हो पाता है, जिसमें तनाव प्रबंधन तथा अपनी व दूसरों की भावनाओं के प्रबंधन की क्षमता अधिक होती है। आधुनिक शासन की चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम एक लचीला प्रशासनिक ढांचा बनाने के लिए व्यापक सुधारों की आवश्यकता को उजागर करती है। नौकरशाहों को विषाक्त कार्य वातावरण, मौखिक दुर्व्यवहार और लगातार मल्टीटास्किंग का सामना करना पड़ता है, जो मानसिक स्वास्थ्य को काफी प्रभावित करता है। ज्यादातर आईएएस अधिकारी राहत कार्यों का प्रबंधन करने के लिए लंबे समय तक अनिद्रा और बर्नआउट का शिकार होते है। तेजी से विकसित हो रही हितधारक मांगें और सीमित प्रशिक्षण नौकरशाहों के तनाव को बढ़ाते हैं और अनुकूलन क्षमता को कम करते हैं। महामारी के दौरान ज़िला कलेक्टरों को वैक्सीन लॉजिस्टिक्स से जूझना पड़ा, जो संकट प्रबंधन में पुराने प्रशिक्षण को उजागर करता है। हथियारबंद नियमों के तहत पूछताछ किए जाने का डर तनाव को बढ़ाता है और निर्णय लेने को कमजोर करता है। एक आईआरएस अधिकारी को नई कर नीतियों को लागू करने में प्रक्रियात्मक खामियों पर असंगत जांच का सामना करना पड़ता है। एक अस्थिर, अनिश्चित, जटिल, अस्पष्ट दुनिया उनकी चुनौतियों को और खराब कर देती है।

जलवायु परिवर्तन नीतियों को संभालने वाले नौकरशाहों को अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण वैज्ञानिक डेटा को एकीकृत करने में संघर्ष करना पड़ता है। शारीरिक थकान, चिड़चिड़ापन और कम रचनात्मकता जैसे लक्षण शासन कार्यों को प्रभावी ढंग से संभालने की उनकी क्षमता को कम करते हैं। परियोजनाओं का प्रबंधन करने वाले नौकरशाह लगातार तनाव से सम्बंधित थकान के कारण कम दक्षता का शिकार आते हैं। शासन की दक्षता पर नौकरशाही के बर्नआउट का नकारात्मक प्रभाव बर्नआउट प्रतिक्रिया समय को कम करता है, जिससे नीति कार्यान्वयन और सार्वजनिक सेवा वितरण में देरी होती है। 2018 के केरल बाढ़ के दौरान धीमी कार्यवाही ने राहत प्रयासों में देरी की और सार्वजनिक शिकायतों को बढ़ा दिया। बर्नआउट के कारण जोखिम का डर शासन प्रक्रियाओं में प्रयोग को रोकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शासन परियोजनाओं में नवीन विचारों की कमी के कारण इष्टतम परिणाम सामने आए। तनाव से सम्बंधित अकुशलता जनता के अविश्वास और शासन के प्रति असंतोष को बढ़ावा देती है पूर्वोत्तर राज्य के एक स्वास्थ्य विभाग ने मलेरिया के प्रकोप के दौरान खराब समन्वय की सूचना दी, जिससे प्रतिक्रिया उपायों पर असर पड़ा। थकान और मानसिक तनाव से महत्त्वपूर्ण नीतिगत त्रुटियों का जोखिम बढ़ जाता है, जिससे शासन की गुणवत्ता कम हो जाती है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना को लागू करने में त्रुटियों के कारण हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए वित्तीय बहिष्कार हुआ। एक लचीले प्रशासनिक ढांचे के लिए व्यापक सुधार करना बहुत जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए गोपनीय परामर्श सेवाएँ और अनिवार्य कल्याण कार्यक्रम शुरू करें। नौकरशाहों के लिए कर्नाटक की पायलट तनाव-प्रबंधन कार्यशालाओं ने 2023 में अधिकारियों के मनोबल और दक्षता में सुधार किया हैं। उभरती चुनौतियों, नेतृत्व और प्रौद्योगिकी पर नियमित प्रशिक्षण को संस्थागत बनाना, दक्षता बढ़ाने के लिए स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का प्रबंधन करने वाले अधिकारियों के लिए एआई एकीकरण कार्यशालाएँ आयोजित करना, नवाचार के लिए ठोस पुरस्कार प्रदान करना और निर्णय लेने में प्रयोग के लिए सुरक्षित मार्जिन की अनुमति देना अति आवश्यक हैं। महाराष्ट्र के अभिनव ग्रामीण आवास योजना अधिकारियों को विशेष मान्यता मिली, जिससे साहसिक शासन दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला। विनियामक भय को कम करने और स्वायत्त निर्णय लेने को प्रोत्साहित करने के लिए सेवा नियमों को सरल और आधुनिक बनाएँ। गुजरात ने अपनी सौर ऊर्जा नीतियों में नौकरशाही प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया, परियोजना अनुमोदन में तेजी लाई। लचीली समय-सारिणी और चिंतन के लिए व्यक्तिगत समय को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ स्थापित करें।

नौकरशाही की थकान से निपटने के लिए मानसिक स्वास्थ्य, कौशल विकास और नवाचार के लिए प्रोत्साहन को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है ताकि शासन दक्षता को बढ़ाया जा सके। एक सहायक ढांचा सिविल सेवकों को स्पष्टता और लचीलेपन के साथ प्रदर्शन करने के लिए सशक्त बनाता है। जैसा कि गांधीजी ने कहा था, ₹खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की सेवा में खुद को खो देना।₹ उनकी भलाई सुनिश्चित करने से नौकरशाहों को नए उद्देश्य और जोश के साथ राष्ट्र की सेवा करने में मदद मिलेगी। लचीलेपन में सुधार और तनाव को कम करना जमीनी स्तर के सिविल सेवकों में अवसाद और चिंता को रोकने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये निष्कर्ष समाज और सरकारी विभागों को जमीनी स्तर के सिविल सेवकों की मानसिक स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर ढंग से समझने और सम्बंधित प्रबंधन और रोकथाम उपायों के निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने और जमीनी स्तर के सिविल सेवकों के लिए उच्च-स्तरीय कार्य वातावरण बनाने में मदद कर सकते हैं।

-प्रियंका सौरभ

नौकरशाहों को विषाक्त कार्य वातावरण, मौखिक दुर्व्यवहार और लगातार मल्टीटास्किंग का सामना करना पड़ता है, जो मानसिक स्वास्थ्य को काफी प्रभावित करता है। ज्यादातर आईएएस अधिकारी राहत कार्यों का प्रबंधन करने के लिए लंबे समय तक अनिद्रा और बर्नआउट का शिकार होते है। तेजी से विकसित हो रही हितधारक मांगें और सीमित प्रशिक्षण नौकरशाहों के तनाव को बढ़ाते हैं और अनुकूलन क्षमता को कम करते हैं। थकान और मानसिक तनाव से महत्त्वपूर्ण नीतिगत त्रुटियों का जोखिम बढ़ जाता है, जिससे शासन की गुणवत्ता कम हो जाती है। एक लचीले प्रशासनिक ढांचे के लिए व्यापक सुधार करना बहुत जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए गोपनीय परामर्श सेवाएँ और अनिवार्य कल्याण कार्यक्रम शुरू करें। उनकी भलाई सुनिश्चित करने से नौकरशाहों को नए उद्देश्य और जोश के साथ राष्ट्र की सेवा करने में मदद मिलेगी।

घूँघट की बगावत

05 जनवरी 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

भारत सभी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाला देश

महात्मा गांधी के पसंदीदा भजन- वैष्णव जन तो तेने कहिये जे पीड़ परायी जाणे रे अर्थात दूसरों की पीड़ा समझने वाला ईश्वर के समान होता है - इसे भारत सही अर्थों में चरितार्थ कर रहा है। भारत हमेशा से विश्व बंधुत्व की भावना के सिद्धांत को अपनाकर उसी मार्ग पर चलाता आ रहा है। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो हमेशा से सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करता रहा है।

दुनिया के किसी भी देश में कैसा भी संकट आया हो भारत उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नजर आता है। इसी को कहते हैं विश्व बंधुत्व की भावना । वैश्विक परिवार दिवस यदि दुनिया का कोई देश सही मायने में मनाता है तो वह भारत ही हैं। भारत में आज भी अतिथि देवो भव की भावना जिंदा है। यहां के लोग स्वयं भूखे रहकर अतिथियों को भोजन करवाना अपना परम धर्म समझते रहे हैं। वैश्विक परिवार का अर्थ है वसुधैव कुटुम्बकम इसका मूल सिद्धांत यह है कि संपूर्ण मानवता एक परिवार है। इस विचारधारा के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी राष्ट्र, जाति, या धर्म से हो, एक ही व्यापक परिवार का हिस्सा है। इस सिद्धांत के अनुसार, विश्व में सभी का समान महत्व है और हर किसी को समान सम्मान मिलना चाहिए।

दुनिया भर में लोग नए साल की पहली सुबह का आनंद उठाते हैं। लोग अपने दोस्तों, परिवार और करीबी लोगों के इस खास दिन का जश्न मनाते हैं। नए साल के साथ ही साल के पहले दिन यानी एक जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस भी मनाया जाता है। हर साल एक जनवरी को मनाए जाने वाले इस दिवस के जरिए परिवारों के माध्यम से राष्ट्रों और संस्कृतियों में एकता, समुदाय और भाईचारे की भावना पैदा करता है। दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है कि एक परिवार का निर्माण हो। ताकि विश्व में शांति की स्थापना होने के साथ ही हिंसा भी कम की जा सकें। जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मनाती है। उसी दिन पूरे विश्व में वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। ताकि विश्व में रहने वाले सभी लोग एक परिवार की तरह रहें। इस तरह विश्व के सभी राष्ट्रों और समुदाय में भाईचारे की भावना पैदा हो सके। वैश्विक परिवार दिवस जिसे विश्व शांति दिवस के रूप में भी जाना जाता है। दुनिया में सद्भाव और एकता की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए हर साल मनाया जाता है। यह दुनिया के एक वैश्विक गांव के विचार पर जोर देता है। जिसमें नागरिकता, सीमा या नस्ल की परवाह किए बिना हम सभी एक परिवार हैं। एक खुशहाल परिवार वह परिवार नहीं है जिसमें हर कोई एक दूसरे के जैसा सोचता, काम करता, महसूस करता या व्यवहार करता हो। एक खुशहाल परिवार की एक पहचान यह है कि पूरा परिवार एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार करता हैं।

यह दिन पूरे विश्व को एक परिवार मानता है। वैश्विक परिवार दिवस को शांति और साझाकरण के वैश्विक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बहुसंस्कृतिवाद, बहुलवाद को बढ़ावा देना और शांति और सद्भाव के साथ एक-दूसरे के साथ रहना सिखाना है। यह दिन विश्व के एक वैश्विक परिवार होने के विचार को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य एकजुट होना और इस विचार को बढ़ावा देकर शांति का संदेश फैलाना है कि पृथ्वी एक वैश्विक परिवार है। ताकि दुनिया को सभी के लिए रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाया जा सके। वैश्विक परिवार दिवस की उत्पत्ति दो पुस्तकों में हुई थी। पहली 1996 में अमेरिकी लेखकों स्टीव डायमंड और रॉबर्ट एलन सिल्वर-स्टीन द्वारा लिखित वन डे इन पीस 1 जनवरी 2000 नामक बच्चों की किताब थी। वहीं दूसरी किताब अमेरिकी शांति कार्यकर्ता और लेखक लिंडा ग्रोवर का 1998 का यूटोपियन उपन्यास ट्री आइलैंडरू ए नॉवेल फॉर द न्यू मिलेनियम थी। विशेष रूप से ग्रोवर ने 1 जनवरी को शांति के वैश्विक दिवस के रूप में स्थापित करने काफी अहम भूमिका निभाई थी। इन किताबों के विचारों के आधार पर ही 1997 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 जनवरी को शांति का एक दिन मनाने की घोषणा की।

बाद में 1999 में संयुक्त राष्ट्र और इसके सदस्य देशों ने पहली बार वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। इस दिवस की सफलता को देखते हुए साल 2001 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया। इसके बाद से हर साल एक जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नए साल की शुरूआत के साथ ही इस दिन को मनाने का मकसद एक ऐसे समाज की स्थापना करने का प्रयास है जहां सिर्फ शांति हो।

हालांकि यह एक नई शांतिपूर्ण दुनिया की शुरूआत थी और 1999 में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों को शांति निर्माण की दिशा में रणनीति विकसित करने के लिए उस विशेष वर्ष के पहले दिन को औपचारिक रूप से समर्पित करने का निमंत्रण मिला। इस दिन के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए 2001 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक परिवार दिवस को एक वार्षिक कार्यक्रम घोषित किया गया। पहला वैश्विक परिवार दिवस पहली बार वर्ष 2000 में एक जनवरी को देखा गया था। तब से हर साल नए साल के पहले दिन को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नए साल के आगाज साथ ही वैश्विक परिवार दिवस भी मनाया जाता है। वैश्विक परिवार दिवस को हर साल एक जनवरी को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया के सभी देशों, धर्मों के बीच शांति की स्थापना करते हुए युद्ध और अहिंसा को टालना है। साथ ही यह भी कोशिश है कि आपसी मतभेदों को बात-चीत के जरिए से निपटाया जाए और एक शांतिपूर्ण समाज की स्थापना की जा सके। इस दिन के लिए परिवार को काफी अहम माना गया है। क्योंकि परिवार के जरिए ही विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। वैश्विक परिवार दिवस मनाने का सबसे अच्छा तरीका अपने परिवार के साथ दिन बिताना है। इस दिन लोग एक साथ रात्रिभोज की योजना बनाते हैं और अन्य पारिवारिक गतिविधियों का आनंद लेते हैं जो उनके बंधन को मजबूत करते हैं और शांति को बढ़ावा देते हैं।

परिवार के साथ मनोरंजक गतिविधियों में एक साथ शिविर लगाना या एक साथ खाना बनाना, पर जाना, ट्रेक और बहुत कुछ शामिल हो सकता है। इस दिन को समुदाय के हिस्से के रूप में मनाने के लिए आप उन संगठनों के लिए स्वयंसेवक बन सकते हैं जो समुदाय का निर्माण करते हैं, हिंसा को कम करते हैं और अपने परिवार के साथ सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं। आप वैश्विक शांति की दिशा में प्रयासों के बारे में कोई भी फिल्म देख सकते हैं।

कांग्रेस नेतृत्व को नकारने लगे गठबंधन के दल

जून 2023 में 26 विपक्षी दलों के साथ बना इंडिया गठबंधन अब टूट के कगार पर खड़ा है। लोकसभा चुनाव में मिली हार और उसके बाद हरियाणा व महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हुई पराजय ने इस गठबंधन को कमजोर कर दिया है। इसी के चलते कांग्रेस के सहयोगी दल ही उसकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाकर अलग राह पकड़ने के संकेत दे रहे हैं। हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने तो कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर निकलवाने तक की धमकी दे दी है। कांग्रेस द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा के बाद से ही आम आदमी पार्टी कांग्रेस से खासी नाराज नजर आ रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस जिस तरह से चुनाव लड़ रही है उससे भाजपा को लाभ मिल रहा है। कांग्रेस नेता अजय माकन व संदीप दीक्षित के बयान विपक्ष को कमजोर करने के लिए भाजपा के कहने पर दिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद चंद पवार), नेशनल कांफ्रेंस तो खुलकर कांग्रेस की मुखालफत करने लगी है।

हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी जीत तय मानकर आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। जिसके चलते आम आदमी पार्टी ने कई सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़कर 1.8 प्रतिशत वोट प्राप्त किए थे। जबकि हरियाणा में कांग्रेस को 39.34 प्रतिशत वोट व भाजपा को 39.94 प्रतिशत वोट मिले थे। यदि हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी से समझौता करके चुनाव लड़ती तो निश्चय ही सरकार बन सकती थी। मगर कांग्रेस ने अवसर गवां दिया और वहां भाजपा ने आसानी से तीसरी बार पहले से भी अधिक बहुमत से सरकार बना ली। उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव में तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी थी। जबकि लोकसभा चुनाव कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर ही लड़ा था। महाराष्ट्र में कांग्रेस नीत महा विकास अघाड़ी की करारी हार होने के बाद शिवसेना (यूबीटी) ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस ने हरियाणा में आप और समाजवादी पार्टी को सीट ना देकर गलती की थी। पार्टी के मुखपत्र सामना में भी लिखा गया कि कांग्रेस नेताओं के अति आत्मविश्वास और घमंड ने हरियाणा में हार के लिए भूमिका निभाई। पार्टी नेता संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस को लगने लगा था कि वह अकेले ही जीत सकती है। इसलिए किसी को भी सत्ता में भागीदार बनाना उचित नहीं समझा था।

कांग्रेस पार्टी इन दिनों अपने ही साथी दलों के निशाने पर है। भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों के संयुक्त इंडिया गठबंधन में शामिल विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं द्धारा कांग्रेस पार्टी से इंडिया गठबंधन का नेतृत्व वापस लेने की मांग की जा रही है। इंडिया गठबंधन में शामिल बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी खुले आम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठा रही है। उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कांफ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी को इंडिया गठबंधन के नेता पद से हटाने की मांग की हैं। ममता बनर्जी की मांग के समर्थन में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी अपनी सहमति जताई है। इससे इंडिया गठबंधन की स्थिति लगातार कमजोर हो रही है।

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस कुल 329 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। जिसमें से 145 सीटों पर बिना किसी गठबंधन की अकेले चुनाव लड़ी थी। जिसमें कांग्रेस 37 सीटों पर चुनाव जीती थी। कांग्रेस का बिना किसी दल से गठबंधन में जीत का रेशियो 25.52 प्रतिशत रहा था। जबकि कांग्रेस 184 सीटों पर साथी दलों से गठबंधन करके चुनाव लड़ी थी। इसमें कांग्रेस ने 62 सीट जीती थी और जीत का रेशियो 33.75 प्रतिशत रहा था। इस तरह से देखे तो कांग्रेस पार्टी को अकेले चुनाव लड़ने की बजाय गठबंधन साथियों की बदौलत बड़ी जीत हासिल हुई थी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 13 करोड़ 67 लाख 59 हजार 64 यानी 21.29 प्रतिशत वोट मिले थे। गठबंधन करने के कारण 2019 की तुलना में 2024 में कांग्रेस को 1.91 प्रतिशत अधिक वोट मिले थे।

कांग्रेस पार्टी ने पंजाब, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना व पश्चिम बंगाल में अपने बूते चुनाव लड़ा था। जबकि बिहार, गुजरात हरियाणा झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, पांडिचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। अंडमान निकोबार दीप समूह, आंध्र प्रदेश, दादरा नगर हवेली व दमन दीव, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड ऐसे प्रदेश है जहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सका था।

हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका महाराष्ट्र में लगा जहां उनकी सीटे 44 से घटकर 16 रह गई। महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना (यूबीटी) व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के साथ महाविकास अघाड़ी बनाकर चुनाव मैदान में उतरी थी। वहां कांग्रेस सबसे अधिक 101 सीटों पर चुनाव लड़ी जिसमें महज 16 सीट ही जीत पाई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 80 लाख 20 हजार 921 वोट मिले जो कुल मतदान का 12. 42 प्रतिशत थे। महाराष्ट्र में कांग्रेस की जीत का स्ट्राइक रेट 15.38 प्रतिशत ही रहा।

संसद का शीतकालीन सत्र का समापन हो चुका है। जिसमें अधिकांश समय कांग्रेस ने अदानी मुद्दे को लेकर संसद नहीं चलने दी। इससे संसद का कार्य पूरी तरह प्रभावित रहा। इसको लेकर भी कांग्रेस की सहयोगी तृणमूल कांग्रेस, सपा ने कांग्रेस को घेरते हुये आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर बहस नहीं होने देना चाहती है तथा सिर्फ अदानी मुद्दे को ही जिंदा रखे हुए हैं। यदि संसद चलती तो कई तरह के मुद्दों पर सरकार को घेरा जा सकता था।

इंडिया अलायंस में जिस तरह की खटपट वर्तमान समय में चलने लगी है वह अलायंस के लिए शुभ नहीं मानी जा सकती है। अलायंस में शामिल दल ही विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व को नकारने लगे है इससे बुरी बात कांग्रेस पार्टी के लिए और क्या हो सकती है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर इंडिया गठबंधन बनाकर केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी। वही गठबंधन अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है।

आने वाले समय में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं। वहां भाजपा चुनाव जीतने की पूरी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि वह दिल्ली की सत्ता पर फिर से काबिज हो। मगर कांग्रेस का रवैया देखकर आम आदमी पार्टी भी सकते में है। पार्टी के नेता कांग्रेस को वोट कटवा के रूप में देख रहे हैं तथा खुले आम भाजपा की बी टीम के रूप में काम करने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दो सूची जारी कर दी है। शेष सीटों पर भी जल्दी ही प्रत्याशियों के नाम घोषित करने की तैयारी चल रही है। यदि दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी पराजित हो जाती है तो इंडिया गठबंधन के ताबूत में वह आखरी कील साबित होगी। कांग्रेस को यदि इंडिया गठबंधन को बचाना है तो अपने सहयोगी क्षेत्रीय दलों की भावनाओं को समझ कर फैसला करना होगा। तभी कांग्रेस अपने राजनीतिक वजूद को बचा पाएगी। इंडिया गठबंधन टूटने की स्थिति में कांग्रेस का भी कमजोर होना तय माना जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस अकेले भाजपा से मुकाबला नहीं कर सकती है। गठबंधन के साथी दलों की मदद से ही कांग्रेस मजबूत हो सकेगी इस बात से कांग्रेस नेता भी अच्छे से वाकिफ है।

ऐतिहासिक रहा खेल जगत के लिए पिछला वर्ष

2024 में खेलों में तकनीकी उन्नति ने निर्णायक भूमिका निभाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और वर्चुअल रियलिटी ने खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और प्रदर्शन विश्लेषण को नई दिशा प्रदान की। इसके अलावा दर्शकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एआर (ऑगमेंटेड रियलिटी) तकनीक का उपयोग किया गया। विश्वनाथन आनंद के बाद इस वर्ष शतरंज के नए चैंपियन उभरकर दुनिया के सामने आए और शतरंज ने खेल प्रेमियों को जश्न मनाने का भरपूर मौका दिया । हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में 45वें चेस ओलंपियाड का आयोजन हुआ था, जिसमें पुरुष वर्ग में 195 देशों की 197 टीमों और महिला वर्ग में 181 देशों की 183 टीमों ने हिस्सा लिया था। भारत की पुरुष और महिला दोनों ही टीमों ने सितंबर में इस ओलंपियाड में पहली बार स्वर्ण पदक जीते, वहीं डी गुकेश और कोनेरू हम्पी ने दिसंबर में विश्व खिताब के साथ नई ऊंचाईयों को छुआ। 12 दिसंबर को सिंगापुर में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप केश ने महज 18 वर्ष की आयु में पिछली बार के शतरंज चैंपियन चीन के डिंग लिरेन को हराकर सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बनकर नया इतिहास रचा। वह विश्वनाथन आनंद के बाद वैश्विक खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय बने, वहीं 37 वर्षीया हम्पी ने 28 दिसंबर को अपने कैरियर में दूसरी बार महिलाओं का रैपिड विश्व खिताब जीता।

पिछले साल भारत वनडे विश्व कप 2023 का खिताब जीतने से चूक गया था लेकिन इस वर्ष आ-ईसीसी ट्रॉफी जीतने का 11 वर्ष का सूखा समाप्त करने में भारत सफल हुआ। आखिरी बार महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में भारत ने 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी। रोहित शर्मा की कप्तानी में 30 जून 2024 को भारतीय टीम ने बारबाड-ोस में दक्षिण अफ्रीका को मात देकर टी20 विश्व कप का खिताब जीता। इसी प्रकार भारतीय हॉकी टीम ने पांचवीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। भारत की ओर से जुगराज सिंह ने गोल दागा था, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने चीन को 1-0 से मात देते हुए यह खिताब अपने नाम किया। टेनिस में रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में इटली के सिमोन बोलेली और वावसोरी को मात देकर मेंस डबल्स का खिताब जीता और ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी बने। उन्होंने 43 वर्ष की उम्र में यह खिताब अपने नाम किया।

2024 का वर्ष खेल जगत के लिए कई मायनों में अद्वितीय, ऐतिहासिक और प्रेरणादायक रहा। यह वर्ष न केवल नई उपलब्धियों और नए रिकॉर्ड का गवाह बना बल्कि कई युवा खिलाड़ियों के उदय के अलावा खेल में नई तकनीकों के समावेश का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। खेल संस्कृति में बदलाव और तकनीकी उन्नति के कारण खेलों के अनुभव को नई ऊंचाईयां मिली। वर्ष 2024 भारतीय खेलों में क्रिकेट, ओलंपिक, पैरालंपिक, शतरंज ओलंपियाड और फिडे विश्व चैंपियनशिप में सफलता के लिए याद किया जाएगा। भारतीय एथलीटों ने इस वर्ष विभिन्न अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। वॉलीबॉल और टेबल टेनिस जैसे खेलों में भी भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। क्रिकेट से लेकर टेनिस, हॉकी, शतरंज के अलावा भारत ने पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक में भी अपना लोहा मनवाया। भारत का इन खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन रहा, जिससे समस्त देशवासी गौरवान्वित हुए। भारत में आयोजित एशियाई खेल और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप ने वैश्विक स्तर पर भारत को एक प्रभावशाली खेल मेजबान के रूप में स्थापित किया। एक क्रिकेट विश्व कप, 6 ओलंपिक पदक, 29 पैरालंपिक पदक और दो शतरंज विश्व चैंपियनशिप सहित 2024 ने भारतीय खेल प्रश-ंसकों को जश्न मनाने के कई ऐसे अवसर प्रदान किए, जिससे खेलों की दुनिया में भारत का भविष्य उज्जवल नजर आता है।

जहां तक ओलंपिक और पैरालंपिक में भारत के प्रदर्शन की बात है तो पूरी उम्मीद थी कि भारत इस वर्ष पेरिस में ओलंपिक में नया इतिहास लिखेगा लेकिन 206 देशों के बीच भारत 71वें स्थान पर रहा और भारत का अभियान 1 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ समाप्त हो गया जबकि टोक्यो ओलंपिक में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य सहित 7 पदक जीतने में सफल हुआ था। महिला पहलवान विनेश फोगाट का 100 ग्राम वजन अधिक होने का मामला भारत की पदक उम्मीदों पर सबसे ज्यादा भारी पड़ा था क्योंकि उनके स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीदें लगभग पक्की हो चुकी थी। पेरिस ओलंपिक में भारत भले ही टोक्यो ओलंपिक के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सका लेकिन पुरुष हॉकी टीम का लगातार दूसरी बार पदक जीतना भारत के बेहद महत्वपूर्ण रहा। निशानेबाज मनु भाकर ने तो एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतकर सनसनी मचा दी। वह एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी। टोक्यो ओलंपिक के गोल्डन ब्वॉय नीरज चोपड़ा से स्वर्ण पदक जीतने की सबसे ज्यादा उम्मीदें थी लेकिन वह रजत पदक ही हासिल कर सके। उनके अलावा शूटिंग में सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले, कुश्ती में अमन सहरावत और पुरूष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में पदक जीते।

पेरिस ओलंपिक के बाद पैरालंपिक खेलों का महाकुंभ तो भारत के लिए अविस्मरणीय बन गया। दरअसल पहली बार हमारे पैरा खिलाड़ी कीर्तिमानों, उपलब्धियों और पदकों का अभूतपूर्व अध्याय रचने में सफल हुए। दिव्यांग होने के बावजूद उन्होंने दिव्यता के साथ जो सफलताएं अर्जित की, वह तमाम लोगों के लिए मिसाल बनी। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक सहित कुल 29 पदक जीते और पदक तालिका में भारत 18वें स्थान पर रहा। इस-ासे पहले टोक्यो पैरालंपिक में 2020 में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण सहित कुल 19 पदक हासिल किए थे। पेरिस में 17वें पैरालंपिक में 22 खेलों की कुल 549 प्रतिस्पधाओं में दुनियाभर से 4463 दिव्यांग खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और 29 पदक जीतकर अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन करते हुए साबित कर दिखाया कि वे दिव्यांग, आधे-अधूरे और असहाय भले ही हैं लेकिन उनके भीतर हौंसलों की कोई कमी नहीं है। पेरिस पैरालंपिक खेलों में अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, मरियप्पन थंगावेलु, शीतल देवी, नितेश कुमार, प्रवीण कुमार, नवदीप सिंह, हरविंदर सिंह, धरमबीर जैसे पैरा खिलाड़ी अपने यादगार प्रदर्शन के कारण नए नायक बनकर उभरे।

पेरिस ओलंपिक में भारत के पदकों की संख्या बेशक कम रही लेकिन शूटिंग, कुश्ती, हॉकी के अलावा कई अन्य खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखते हुए भविष्य में खेलों की दशा और दिशा सुधरने की उम्मीदें बलवती हुई हैं। मनु भाकर ने ओलंपिक में दो पदक जीतकर भारत की बेटियों को खेलों के प्रति आकर्षित होने का बेहतरीन अवसर प्रदान किया है। ओलंपिक में मनु की सफलता देश की आधी आबादी के लिए बहुत प्रेरणादायी है और अब जरूरत है कि ऐसे सुअवसरों का लाभ उठाकर देशभर में विभिन्न खेलों में ऐसा माहौल बनाया जाए ताकि प्रतिभाशाली लड़कियां आगे आएं और आने वाले समय में तमाम अंतरराष्ट्रीय स्पधाओं में महिलाओं का डंका भी बजता दिखाई दे।

कुल मिलाकर, 2024 का साल खेलों के प्रति भारत और विश्व के दृष्टिकोण को बदलने वाला साबित हुआ। यह साल न केवल अनेक उपलब्धियों से भरा रहा बल्कि इसने भविष्य के लिए नई प्रेरणाएं और दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किए। खेल जगत को इस वर्ष से जो ऊर्जा और उत्साह मिला, वह आने वाले वर्षों में और भी ऊंचाईयां छूने में सहायक होगा। हालां-कि भारत को खेल महाशक्ति बनने से पहले अभी काफी कुछ करने की जरूरत है।

रेवड़ी 'राजनीति' के औचित्य का नहीं, उसके आस्तित्व का प्रश्न

सरकार द्वारा राशन बांटे जाने को रेवड़ी न समझ कर गरीबों की अनिवार्य सहायता समझी जाती थी लेकिन जैसे-जैसे समय गुजरता गया धीरे-धीरे राजनीतिक पार्टियों ने सिर्फ बोट पाने के लिए ही मुफ्त की योजनाओं की घोषणा शुरू कर दीं।तमिलनाडु आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में मुफ्त बांटे जाने वाली सामग्रियों की सूची लंबी ही होती जा रही है। इन सबका प्रभाव पूरे देश की राजनीति पर पड़ना था। दक्षिण भारत की ही तरह उत्तर भारत के राज्यों की सरकार इस 'मुफ्त बाटो रेवड़ी राजनीति के सहारे ही और बिगड़ी। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और कांशीराम-मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने भी खुल कर रेवड़ी राजनीति ही की। बिहार में भी बालू यादव और नीतीश कुमार ने भी कई मुफ्त की योजनाएं लागू की और इसका जबरदस्त चुनावी लाभ भी लिया। मध्य-प्रदेश और राजस्थान में इसके अलग-अलग रूप देखने को मिले। जनता के नजरिये से देखें तो जहां छोटे-छोटे राजनीतिक दलों पर मुफ्त बांटने की नीति की राजनीति को आसानी से रेवड़ी राजनीति कह दिया जाता है वहीं कांग्रेस और भाजपा जैसे बड़े राजनीतिक दल इस कदम को लोक कल्याण के रूप में पेश करने में सफल हो जाते हैं। आम जनता लोककल्याण और रेवड़ी के अंतर को बहुत सूक्ष्मता से नहीं समझती। यह अर्थशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों द्वारा ही सटीकता और सूक्ष्मता से समझाया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अंततः रेवड़ी बांटने की राजनीति का दूरगामी असर नकारात्मक हो होता है और देश की आर्थिक व्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ता है। जनता को तात्कालिक राहत देने के नाम पर सरकारी खजाने को खर्च किया जाता है और लंबी अवधि की विकास योजनाओं के लिए धन का अभाव हो जाता है इससे कुल मिलाकर देश और राज्यों में नौकरियों तथा रोजगार के अवसरों की कमी ही होती है। स्थाई विकास संरचनाओं का निर्माण करना भी मुश्किल होने लगता है। इसी साल फरवरी में दिल्ली में नई सरकार का गठन होता है और संभवतः प्रथम या द्वितीय सप्ताह तक चुनाव करा लिए जाएंगे। सभी प्रमुख पार्टियों में कमर कस ली है और पूरी तरह से चुनावी मूड और मोड में आ चुकी है।

घोषणाओं और वादों की झड़ियां लगनी शुरू हो गई हैं। आरोपों और प्रत्यारोपों की बाढ़ भी आने वाली है। सबसे दिलचस्प बीज तो इस विल्ली चुनाव में देखने को मिलने वाली है वो रेवड़ी राजनीति ही होगी। रेवड़ी राजनीति यूं तो सभी पार्टियां करती हैं। लेकिन इसके सबसे बड़े धुरंधर खिलाड़ी के रूप में अरविंद केजरीवाल ने अपने आपको स्थापित कर लिया है। केजरीवाल ने अपनी पार्टी को बहुत हो कम समय में दिल्ली की सर्व प्रमुख पार्टी बना दिया थे। लगातार दिल्ली में भारी बहुमत की सरकार बनाने में सफल रहे। भाजपा को पूरे देश में मिले प्रचंड बहुमत के बावजूद दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आप को पछाड़ पाने में सफलता नहीं मिल पाई। इसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि केजरीवाल ने दिल्ली की आबादी और मतदाताओं की संख्या के आर्थिक वर्गीकरण को अच्छे से समझते हुए रेवड़ी को अपना हथियार बनाया। जहां गरीबों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 20 हजार लीटर पानी को देने की घोषणा किया। वहीं मतदाताओं को स्त्री-पुरुष के नए वोट बैंक के रूप में विभाजित करते हुए बसों और मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सौगात देने का वादा किया। इस रेवड़ी राजनीति का लाभ भी केजरीवाल को ही मिला। रेवड़ी राजनीति की जानी चाहिए था नहीं, रेवड़ी राजनीति उचित है या अनुचित रेवड़ी राजनीति के लाभ ज्यादा हैं या हानि ज्यादा है ये सभी प्रश्न अपनी जगह हैं और सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली के आगामी चुनाव में इस रेवड़ी राजनीति का प्रभाव छोड़ेगा या नहीं और अगर प्रभाव पड़ेगा तो कितना प्रभाव पड़ सकने की संभावना है। ये सभी प्रश्न एक दूसरे से गहरे से जुड़े हैं। सत्य यही है कि रेवड़ी राजनीति का तात्कालिक रूप से लाभ लेने की राजनीति है जहां राजनीतिक दल या सरकार जनता में तुरन्त लोकप्रियता हासिल काने के लिए मुफ्त की घोषणाएं करती है। उनका मकसद यही होता है कि उनकी लोकप्रियता बनी रहे और उनको ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सकें। ऐसा नहीं है कि भारतीय राजनीति में रेवड़ी बांटने की राजनीति कोई नई बात नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हो थोड़ी-थोड़ी मात्रा में लोक लुभावन नीतियों की शुरूआत हो गई थी लेकिन तब राजनीति में नैतिकता का ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान था और नये भारत के निर्माण का जोश नेताओं और जनता दोनों में ही ज्यादा था।

अतः जे सब स्वाभाविक लगता है। था। लेकिन वर्तमान भारत की राजनीति में दूर दूर तक सोचने और सूक्ष्मता से विचार करने की प्रवृत्ति कम होती जा रही है। फलतः राजनीतिक दलों के नेता और प्रवक्ता - तेरी रेवड़ी रेवड़ी, मेरी रेवड़ी जनकल्याण का रटा रटाया नारा जपते रहते हैं। जाति और धर्म के नाम पर राजनीतिक दलों द्वारा बनाए जाने वाले तथाकथित वोट बैंक से आनेवाले समर्थक, और कार्यकर्ता अपने नेताओं द्वारा दिए गए निदेर्शों के मुताबिता स्वयं विचार किए बिना तेरी रेवड़ी रेवड़ी, मेरी रेवड़ी जन कल्याण का नारा लगाते हुए चाय की दुकानों और चौक चौराहों चार बहस करते पाए जाते है।

पर्टियों पर जनता का भरोसा कम हुआ'

वर्तमान परिस्थितियों में जो कुछ हाल रहा है, उससे जनता का भरोसा राजनीतिक दलों और नेताओं से उठ गया है। आजादी के बाद यह शिगूफा छोड़ा जा रहा है कि हम गरीबी खत्म कर देंगे। अगर कड़वा सच है कि गरीबी बढ़ती जा रही है। हालांकि समय- समय पर गरीबी की परिभाषा बदलती रहती है। 1960 के दशक में जो गरी बी थी 1990 में वह बदल गई। और आज 2020 के दशक में नहीं है। क्योंकि जरूरतें आदमी की बदलती रहती हैं। जैसे-जैसे जरूरतें बदलेंगी तो स्वाभाविक है कि गरीबी की परिभाषा भी बदल जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर हम लद्दाख को देखें तो वहां किसी परिवार के पास पर्याप्त भोजन नहीं है ऊर्जा नहीं है और पर्याप्त घर नहीं है तो एक दिन भी वह जिंदा नहीं रह सकता क्योंकि वहां के हालात बेहद प्रतिकूल हैं। तो अगर आप देखें कि लद्दाख में गरीब आदमी के पास जरूरी है कि उसके पास घर भी हो, भोजन भी हो, कपड़ा भी हो और ऊर्जा यानी बिजली- ये चारों चीजें हों। अगर ये चारों चीजें उपलब्ध हैं तो हमारे यहां मध्यम श्रेणी में आ जायेगा। तो जो हमारे यहां मिडिल क्लास होगा वह जरूरी नहीं कि लद्दाख में होगा। वहीं अगर हम तमिलनाडु में देखें तो वहां पर एक गरीब आदमी कपडे पहन कर केला खाकर एक झोपड़ी में गुजर बसर करता है। तो गरीबी की परिभाषा जो है वह अलग-अलग जगहों पर अलग अलग होती है और अलग-अलग टाइम में अलग-अलग होती है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गांव से शहर आ गया है तो उसके लिए यहां मोबाइल रखना मजबूरी हो। इससे यह अनुमान नहीं लगा सकते कि वह व्यक्ति अमीर है। हां, अगर बच्चों की पढाई सही हो रही है, चिकित्सा सही हो रही है तो यह मानने में हर्ज नहीं कि गरीबी कम हो रही है। सरकार भले ही कहे कि हमने गरीबी कम कर दी। मगर मेरा यह मानना है कि गरीबी उस मायने में कम नहीं हुई है। अगर पढ़ाई सही हो रहा है या इलाज हो रहा है तो माना जाए कि सरकार के दावों में दम है।

सबसे पहली बात ये है कि दिल्ली में लड़ाई त्रिकोणीय है। कांग्रेस की जो हार हुई और हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी (आप) को भी मोट नहीं दो। या किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं किया उसके बाद से दोनों दलों के बीच रिश्ते मधुर नहीं रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस से मिली उपेक्षा के बाद आप ने भी दिल्ली में यह ऐलान कर दिया कि वह स्वयं कांग्रेस के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगी। इसकी वजह साफ है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत है और एक समय यहां सत्ता में रही कांग्रेस अब दोयम दर्जे की पार्टी हो गई है। तो ये वजह है कि दिल्ली में लड़ाई त्रिकोणीय है क्योंकि कांग्रेस भी अब दांव भी नहीं छोड़ सकती है। उसने अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए हर हाल में चुनावी रणक्षेत्र में अपनी अहमियत बनाएं और बचाए रखनी होगी। उसे लड़ना ही पड़ेगा। हालांकि दिल्ली की सत्ता में बने रहने और उस पर काबिज रहने की मुख्य लड़ाई आप और भाजपा के बीच ही होने की संभावना है। कांग्रेस कमजोर हो गई है। इस बात को मानने में कोई हर्ज नहीं है। पार्टी का संगठनात्मक ढांचा हर जगह कमजोर हो चला है।

स्थानीय स्तर पर उनके कार्यकर्ता कम हैं और जो भी हैं और उनमें उत्साह न हो रह गया है। उदाहरणार्थ महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले लग रहा था कि पार्टी और महाविकास आघाड़ी गठबंधन सत्ता में आ जायेगी मगर ऐसा नहीं हो सका। अंतिम परिणाम ने हर किसी को चौंका दिया। जहां तक मुफ्त में सब चीज उपलब्ध कराने की है तो हर चीज फ्री नहीं होती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां बाजार गरीब लोगों को सपोर्ट नहीं करता है। तो वहां पर सरकार को देना पड़ता है। जैसे-शिक्षा. स्वास्थ्य पीने का पानी, ये सारी चीजें गरीब को मयस्सर नहीं हो पाती उसे मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो असल में रेवड़ी या मुक्त चीजें हम उसको कहेंगे जहां कुछ दिया जा रहा है जिसकी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जैस-साइकिल दे दो लैपटॉप दे दिया या कुछ इस तरह की चीजे दे दो। लेकिन अगर गरीबी ज्यादा है, गरीबों के हमें अगर पैसा देना है जिससे कि वह जरुरी चीजें और खाना पीना हासिल कर सके। ये सारी-तीले मुहैया करा सकें इसकी संभावना हो सकती है।

चूंकि जनता का विश्वास कम हो रहा है तो वह यह नहीं मानती कि सरकार दीर्घ समय के लिए उसे कुछ देगी। जो 75 साल से सरकार वादा कर रही है, वह वादे अभी भी किये जा रहे हैं। अगर सरकार के तरफ से कुछ काम हुआ है तो बहुत कम हुआ है। आज आप क्या दे सकते हैं तो सरकार फ्री बस सेवा दे सकती है या फ्री बिजली और पानी दे सकती है। तो इसे होकर सभी राजनीतिक दलों में होड़ सी लग गई है। कोई भी राजनीतिक पार्टी इस बात से इंकार नहीं कर रही है जिसे देखो वही मुफ्त की घोषणा करने में लगा है।

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना ने सत्ताधारी दलों के लिए क्या किया हर कोई जानता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी का फायदा मिला है। लेकिन फायदा तो हुआ है खासकर महिलाओं को। इसलिए भी जोर शोर से भी है कि राजनीतिक दलों पर भरोसा कम हुआ है। इसलिए वह जल्दी से कुछ ऐसा करना चाहती है जो जनता के दिलो दिमाग पर जल्दी से असर करे। तोदिल्ली में आम आदमी पार्टी ने यही किया और उन्हें इसका फायदा मिला। यही वजह है कि भाजपा और अन्य दल भी इस भेड़ चाल में आगे बढ़-चुके हैं। इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसका चुकसान दूरगामी होगा। इससे बजट पर नकारात्मक असर पड़ेगा।

एक ऐसे भारतीय युग की शुरूआत करें जो खोई समृद्ध विरासत लौटा सके

बीते वर्ष में हमने भारत में दुनिया का सबसे चुनाव कराया, जिससे दुनिया के सामने निरंतर राजनीतिक स्थिरता के प्रति हमारे दृढ़ विश्वास की पुष्टि हुई। लगातार चौथे वर्ष सात प्रतिशत के करीब उच्च आर्थिक विकास दर के साथ भारत ने संरक्षणवाद व राजनीतिक बदलाव के वैश्विक रुझानों को खारिज कर दिया, जैसे फ्रांस और युनाइटेड किंगडम के चुनाव परिणामों में देखा गया था। हम भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद संरचनात्मक सुधारों के साथ अपनी उच्च आर्थिक विकास को नीति जारी रखे हुए हैं। विकास दर पर कुछ मौजूदा विवादों के बावजूद हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस वर्ष भी संभावना है कि- हम 6.6 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ते रहेंगे। राजकोषीय लक्ष्यों के अनुरूप एख रहे हैं। हमारा महंगाई पर भी काबू है। भारत की बेरोजगारी दर हाल में गिरकर आठ प्रतिशत हो गई। हालांकि अधिकांश वित्त वर्ष मे यह ऊंची रही थी। ग्रामीण और शहरी रोजगार की असमानताओं को दूर करने और सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप की जरूरत है। स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और स्थिरता में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी भारत की प्रगति उल्लेखनीय है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम 24 लाख से अधिक परिवारों तक पहुंच गया है जिससे जेब से होने वाले स्वास्थ्य देखभाल खर्च में काफी कमी आ गई है। और स्वास्थ्य संकेतकों में कुछ सुधार दर्ज हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दो करोड़ ढेढ लाख से अधिक किफायती आवास का निर्माण हुआ है। भारत जलवायु के मोर्चे पर भी अपने योगदान के लिए पूरी गंभीरता से प्रतिबद्ध है। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 200 मेगावाट के मील के पत्थर को पार कर गई है। यह सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में विशेष निवेश की वजह से संभव हुआ है। अक्षय ऊर्जा उत्पादन अब राष्ट्रीय कुल उत्पादन क्षमता 452.69 गीगावाट का आधा है। ग्रामीण विद्युतीकरण ने भी लगभग सर्वव्यापी कवरेज हासिल कर लिया है। और सरकारी प्रोत्साहनों द्वारा समर्थित इलेक्ट्रिक वाहन के प्रसार में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विकास की ये घटनाएं उत्साह बढ़ा रही हैं। अब वर्ष 2025 के लिए हमारा क्या लक्ष्य है? क्या हम साल 2047 तक विकासित देश बनेंगे?

का लक्ष्य हासिल कर रहे हैं। करने जा रहे हैं? हां विकसित देश होने के लक्ष्य को हम हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आठ प्रतिशत से अधिक की विकास दर से आगे बढ़ने की जरुरत है। आज हम नए वर्ष में कदम रख चुके हैं और अपनी अनेकानेक उपलब्धियों पर संतुष्टि की भावना के साथ बीते वर्ष 2024 देख रहे हैं। बीते वर्ष की उपलब्धियां हमारे नववर्ष-2025 के लिए योजना बनाने के लिए शुभ संकेत हैं। नववर्ष को आशावाद, उत्साह और उम्मीद की बुनियाद पर खड़ा कर सकते हैं। वर्ष 2025 के लिए आशा है कि हमारी विकास दर सात प्रतिशत के करीब रह सकती है। निःसंदेह, बचत निवेश से हो विकास होता है और इसमें राजकोषीय घाटे के प्रबंधन की जरूरत पड़ती है। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि राजमार्गो, शहरी विकास आदि में पूंजीगत व्यय पर जोर दिया जायेगा। जीएसटी की बढ़ती पहुंच कर संग्रह को बल प्रदान करेगी । प्रत्यक्ष कर संहिता को लागू करना बहुत आवश्यक है जो आयकर वसूली पर निर्णायक प्रभाव डालेगा। हम प्रौद्योगिकी को अपनाने में अग्रणी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और फाइबर ऑप्टिक्स की बढ़ती पहुंच उत्पादकता में निर्णायक बढ़त लाएगी। फिलहाल हमारे सागने चार बड़ी चुनौतियां हैं- सबसे पहली 2025 का भारतीय परिदृश्य बाहरी कारणों से प्रभावित होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर बदलाव का प्रभाव उच्च टैरिफ प्रतिबंधों और मौद्रिक नीति पर पड़ सकता है, जिससे अनिश्चितता को बल मिल सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रबंधन चुनौतीपूर्ण होता जायेगा। वैश्विक अस्थिरता को देखते हुए विकास और मुद्रास्फीति को संतुलित करने में मुश्किल आ सकती है। दूसरी : यूक्रेन और गाजा दोनों जगह युद्ध ऊर्जा सुरक्षा सहित भू-राजनीतिक जोखिम पैदा कर रहा है। तीसरी, जब हमें एक मुक्त अर्थव्यवस्था को बनाए रखना है, तब संरक्षणवादी प्रभाव बहुपक्षीय संस्थानों को बिगाड़ने का काम करते हैं। लेन-देन संबंधी द्विपक्षीय व्यवस्थाओं पर दवाब डालते हैं। अतः इस मोर्चे पर हमें सावधानी से संतुलन बनाकर चलने की जरूरत होगी। अंत में, सबसे बड़ा सवाल यह है कि नवाचार को कैसे बढ़ावा देंगे। प्रौद्योगिकी को कैसे अपनाएंगे और लाभकारी रोजगार कैसे पैदा करेंगे जब अधिकांश अत्याधुनिक तकनीक को विस्थापित करने में लगी है। तब कुशल और गरिमापूर्ण नौकरियों के लिए शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव की जरुरत है। शिक्षा शासन में कौशल विकास हमें वापस योजना बनाने के लिए विवश कर रहे हैं। कर आई तकनीक और अन्य तकनीकी परिवर्तनों के प्रभात को देखते हुए जहां कई तरह के काम करने की जरूरत पड़ सकती है। वही शिक्षा प्रदान करने की क्षमता शिक्षा सुधार और क्रियान्वयन को चुनौतीपूर्ण बनाती है।

मेक इन इंडिया अभियान और उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) भारत को वैश्विक मूल्यवर्धित श्रृंखला से जोड़ने में मदद करेंगे। फिर भी रोजगार और विकास की चुनौती के लिए संवेदनशीलता और सही देखभाल की जरूरत पड़ेगी ।

जारी रहेगी टकराव की राजनीति

यह तय है कि नए वर्ष में वक्फ बोर्ड और एक देश-एक चुनाव विधेयक पर भी जोर आजमाइश जारी रहेगी और समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर भी राजनीति गरमाएगी। इस सबकी छाया वर्ष 2025 पर पड़ेगी ही। आंबेडकर मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान भाजपा-कांग्रेस सांसदों में हुई धक्का-मुक्की मामले में राहुल गांधी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो चुकी है। यह मामला पिछली लोकसभा में मानहानि मामले में राहुल गांधी की सदस्यता समाप्ति के बाद भाजपा-कांग्रेस में चले टकराव के दूसरे संस्करण का रूप ले सकता है। भाजपा मामले को कानूनी रूप देना चाहेगी, जबकि कांग्रेस राजनीतिक। हालांकि अदाणी और ईवीएम मुद्दे पर कांग्रेस आईएनडीआईए में अकेली पड़ती दिख रही है, लेकिन आंबेडकर के मुद्दे को वह फिर ह्यगेम चेंजरह्व बनाना चाहेगी। साझा लाभ देख कर आईएनडीआईए भी आंबेडकर के मुद्दे पर एक स्वर में बोलता नजर आएगा। इसकी पुष्टि इससे होती है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने भगवान का अपमान बताते हुए आंबेडकर के नाम पर स्कालरशिप शुरू करने का ऐलान कर दिया है। निःसंदेह भाजपा भी शांत नहीं बैठने वाली। जाहिर है इस मसले पर टकराव आगे भी देखने को मिलेगा।

नए वर्ष का स्वागत अनेक आशाओं के साथ अवश्य किया जा रहा है, लेकिन बीता वर्ष बता रहा है कि इस नए वर्ष में टकराव की राजनीति जारी रहेगी। शायद आपसी तल्खी और बढ़ जाए। 2024 राजनीतिक विरासत ही कुछ ऐसी छोड़ कर जा रहा है। वैसे राजनीतिक टकराव की नींव वर्ष 2023 में ही तब पड़ गई थी, जब दो दर्जन विपक्षी दलों ने आईएनडीआईए बनाया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गौतम अदाणी के जरिये सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार किया, जिनकी साख भाजपा की सबसे बड़ी पूंजी रही है। बीच-बीच में उजागर अंतर्विरोधों के बावजूद आईएनडीआईए 18वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा को अकेले दम बहुमत पाने से वंचित करने में सफल भी रहा, पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे मित्रों की बदौलत मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। फिर भी लगातार दो लोकसभा चुनावों में पस्तहाल रहे विपक्ष को संजीवनी तो मिल ही गयी। उसका असर भी नई संसद के पहले सत्र में दिखा, जब विपक्ष ज्यादा आक्रामक दिखा, पर फिर समीकरण बदल गए। पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र में प्रचंड जीत से भाजपा ने विपक्ष के उत्साह की हवा निकाल दी। संसद के शीतकालीन सत्र में भाजपा के आक्रामक तेवर भी लौट आए तो आईएनडीआईए में तकरार दरारों में तब्दील होती दिखी। संसद के बीते सत्र में भीमराव आंबेडकर का मुद्दा भी जुड़ गया।

नया साल शुरू होते ही फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव हैं। देश की राजधानी में सत्ता की हैट्रिक करने वाली आप चौथी बार जनादेश मांगेगी, जबकि 27 साल से विपक्ष में बैठी भाजपा दिल्लीवासियों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। यह राजनीतिक शोध का विषय है कि पिछले तीन लोकसभा चुनावों में भाजपा को सभी सात सीटें जिताने वाली दिल्ली उसे विधानसभा चुनावों में क्यों नकारती रही है?

नए साल में दिल्ली के दिल में किसके लिए क्या है, वह तो चुनाव परिणाम बताएंगे, पर यह स्पष्ट है कि भाजपा और आप के बीच राजनीतिक टकराव चरम पर पंहुचेगा। टकराव कांग्रेस और आप के बीच भी बढ़ने वाला है। लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ीं कांग्रेस और आप विधानसभा चुनाव अकेले तो लड़ेंगी ही, एक-दूसरे पर तल्ख आरोप भी लगाएंगी। इसकी शुरूआत हो चुकी है। दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेता अजय माकन ने आप से दोस्ती को गलती मानते हुए केजरीवाल को देश विरोधी करार दे दिया है। आप ने माकन के विरुद्ध कार्रवाई न किए जाने पर गठबंधन से ही कांग्रेस को बाहर करने के लिए अन्य घटक दलों से बात करने की चेतावनी दे दी है। आईएनडीआईए की बदौलत ही 99 सीटों पर पहुंच पाई कांग्रेस के लिए गठबंधन की राह लगातार मुश्किल होती दिख रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में उसने किसी घटक दल को भाव नहीं दिया तो महाराष्ट्र में बड़ा भाई बन बैठी। ऐसे में हार का ठीकरा सबसे ज्यादा उसी पर फूटा। ममता बनर्जी ने गठबंधन के नेतृत्व के लिए दावेदारी जताई तो शरद पवार से लेकर लालू यादव तक ने उनका समर्थन करने में देर नहीं लगाई। उत्तर प्रदेश के नौ विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को एक भी सीट न देकर अखिलेश यादव भी अपनी मंशा जता चुके हैं। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ईवीएम मुद्दे पर कांग्रेस को चुनाव परिणाम स्वीकार करने की नसीहत दे चुके हैं, तो उप मुख्यमंत्री पद मांग रही कांग्रेस से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी खुश नहीं। पिछली बार 70 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस 19 सीटें जीत कर गठबंधन में सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई थी।

इसलिए 2025 के अक्टूबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में लालू-तेजस्वी भी उसे हद में रखना चाहेंगे। बेलगावी अधिवेशन के 100 वर्ष पूरे होने पर वहां आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 2025 को कांग्रेस के सशक्तीकरण का वर्ष बताया है, लेकिन मित्र दलों से उसके बढ़ते टकराव से तो गठबंधन में बिखराव की आशंका गहरा रही है।

एक अप्रिय मुद्दा

ऐसे प्रसंगों से यही धारणा बनती है कि जिन नेताओं ने गांधी-नेहरू परिवार की परवाह नहीं की, उनके साथ उसने बेरुखी और बदसुलूकी की।

मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में कथित गरिमा की कमी का मुद्दा बनाकर कांग्रेस अपने पर लगे सिख विरोधी दंगों के दाग को धोने की कोशिश कर रही हो। वह यह मामला उठाकर पंजाब में सिख समुदाय में नए सिरे से पैठ बनाने की भी कोशिश कर रही है, जिसमें फिलहाल आम आदमी पार्टी का असर है। यह भी ध्यान रहे कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। दिल्ली की कुल आबादी में सिखों की हिस्सेदारी करीब चार प्रतिशत है। साफ है कि मनमोहन सिंह का गरिमामय अंतिम संस्कार न होने का आरोप लगाकर कांग्रेस पंजाब के साथ दिल्ली के सिख मतदाताओं में भी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। यह कोशिश स्वाभाविक है, लेकिन सवाल यह भी है कि नरसिंह राव और विश्वनाथ प्रताप सिंह का निधन नई दिल्ली में होने के बावजूद कांग्रेस ने इन नेताओं का अंतिम संस्कार राजधानी की किसी प्रतिष्ठित जगह कराने की जरूरत नहीं समझी? तब तो दिल्ली और केंद्र में कांग्रेस की ही सरकारें थीं।

विनय सीतापति की लिखी नरसिंह राव की जीवनी हाफ लायनके पन्नों से गुजरेंगे तो पता चलेगा कि नरसिंह राव के निधन के अगले दिन फूलों से सजी सेना की गाड़ी उनके शव को लेकर कांग्रेस मुख्यालय पहुंची और करीब आधे घंटे तक मुख्यालय के गेट पर खड़ी रही, लेकिन गेट नहीं खुला। विनय सीतापति के मुताबिक, नरसिंह राव के स्वजनों ने उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में ही करने की मंशा जताई थी, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार और पार्टी नेतृत्व ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। उस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जिन्हें 1991 में नरसिंह राव ही राजनीति में लेकर आए थे और वित्त मंत्री का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा था। वह अपने पहले राजनीतिक भाग्यविधाता के सम्मान में कुछ कर नहीं पाए। नरसिंह राव आजीवन कांग्रेसी रहे। वह कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और प्रधानमंत्री तो थे ही।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की चिता की आग ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि उनके अंतिम संस्कार को लेकर राजनीति शुरू कर दी गई। इस सियासी विवाद को चिंगारी मिली नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इस बयान से कि देश के पहले सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार कराकर केंद्र सरकार ने उनका अपमान किया है। भाजपा ने जवाबी हमला करते हुए कांग्रेस पर इस मसले को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस और भाजपा में राजनीतिक युद्ध के बीच मनमोहन सिंह का परिवार चुप है। कांग्रेस की ओर से मनमोहन सिंह का कथित तौर पर गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार न होने का आरोप लगाने की एक वजह है। कांग्रेस के दामन पर 1984 के सिख विरोधी दंगों का दाग है। भाजपा सिख विरोधी दंगों को लेकर कांग्रेस को निरंतर कठघरे में खड़ा करती रही है।

नरसिंह राव के पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह का नवंबर 2008 में दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निधन हुआ था। चूंकि उनका परिवार जानता था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को लेकर कांग्रेस कैसा भाव रखती है, इसलिए उसे उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में किए जाने की उम्मीद नहीं थी। उनका अंतिम संस्कार इलाहाबाद (प्रयागराज) में किया गया। शायद कांग्रेस तब भूल गई कि 1987 में कांग्रेस से बगावत करने से पहले तक विश्वनाथ प्रताप सिंह न सिर्फ कांग्रेसी थे, बल्कि एक दौर में इंदिरा गांधी के विश्वासपात्र भी थे। इसी वजह से 1980 में उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का भी दिल्ली में ही निधन हुआ था। कांग्रेसी सरकार ने उनका अंतिम संस्कार न सिर्फ दिल्ली में कराया, बल्कि उनकी समाधि भी दिल्ली में ही बनाई गई। दिलचस्प यह है कि जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान जब मोरारजी देसाई सरकार इंदिरा गांधी से सरकारी आवास खाली कराने की तैयारी में थी, तब चंद्रशेखर ने ही उसे रोका था। प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई का निधन 1995 में मुंबई में हुआ, लेकिन उनका अंतिम संस्कार अहमदाबाद में हुआ। उनके स्वजनों ने न तो दिल्ली में उनके अंतिम संस्कार की मांग रखी और न ही तत्कालीन कांग्रेस सरकार और नेतृत्व ने इसकी जरूरत समझी।

कांग्रेस राज में जिन पूर्व प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं हुआ या नहीं कराया गया, वे सभी कांग्रेसी रहे, लेकिन बाद के दिनों में गांधी-नेहरू परिवार के विरोधी हो गए थे। इसीलिए राजनीतिक हलकों में माना जाता है कि गांधी-नेहरू परिवार के प्रति बगावत की वजह से आखिरी वक्त तक वे कांग्रेस के प्रथम परिवार के निशाने पर रहे। यही वजह है कि कांग्रेस की ओर से मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार पर सवाल उठाए जाने के बाद जवाबी रूप में नरसिंह राव और विश्वनाथ प्रताप सिंह के अंतिम संस्कार और उससे जुड़ी राजनीतिक घटनाएं भी याद कराई जा रही हैं। कांग्रेस को इसे समझना होगा और अप्रिय विवाद उठाने से बचना होगा। वह इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकती कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा है कि उनके पिता के निधन के बाद कांग्रेस कार्यसमिति का औपचारिक शोक संदेश नहीं देना भी एक तरह से उनका अपमान था। ऐसे प्रसंगों से यही धारणा बनती है कि जिन नेताओं ने गांधी-नेहरू परिवार की परवाह नहीं की, उनके साथ उसने बेरुखी और बदसुलूकी की।

नकली और गुणवत्ताहीन दवाओं की रोकथाम का समाधान एकजुटता से संभव

भारत में इन दिनों नकली और गुणवत्ताहीन दवाओं का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है जो नकली दवाओं से प्रभावित न हो। हाल में कोलकाता में कैंसर और मधुमेह जैसे गंभीर बीमारी में उपयोगी होने वाली नकली दवाओं को के-ंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और पश्चिम बंगाल के औषधि नियंत्रण निदेशालय के साझा सहयोग से पकड़ा गया है जिसकी कीमत 6.60 करोड़ बताई गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन से पता चला है कि भारत में कुल बिकने वाली दवाओं में बीस प्रतिशत नकली और गुणवत्ताहीन दवा शामिल हैं। भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में केवल दवा का बाजार लगभग दो लाख करोड़ का है जिसमें नकली और गुणवत्ताहीन दवाओं की भागीदारी 15-20 प्रतिशत के करीब है। भारत में नकली और गुणवत्ताहीन दवाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश,पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्य शामिल है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने केवल 2023 में नकली और गुणवत्ताहीन दवाओं के लगभग पचास हजार मामले दर्ज किए थे। उद्योग संगठन एसोचैम की रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत के दवा बाजार में कुल उपलब्ध एक एक-चौथाई दवा नकली और गुणवत्ताहीन है।

फेक एंड काउंटरफीट ड्रग्स इन इंडिया-बूमिंग बिज' नामक अध्ययन रिपोर्ट के अध्येताओं के अनुसार, भारत में नकली दवाओं का कारोबार 33 प्रतिशत की वृद्धि दर से प्रति वर्ष बढ़ रहा है। नकली दवाओं का बाजार बढ़ने के कई कारण हैं, जिसमें दवा की ऑनलाइन बिक्री, गुणवत्तापूर्ण दवा की अपेक्षा नकली दवा का सस्ती कीमत, दवाओं के प्रति लोगों में जागरूकता की कमी, डॉक्टर द्वारा मरीजों के पर्चे पर लिखे गए दवा के नाम के साथ प्रमाणित दवा कंपनियों का नाम न लिखना, बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में स्वास्थ्य सुविधाओं का उपलब्ध न होना, नकली और

स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है। मनुष्यों को स्वस्थ रहने के लिए उपचार की आवश्यकता भी होती है, लेकिन जब उपचार नकली और गुणवत्ताहीन दवाओं पर आधारित हो तो इंसानों का स्वास्थ्य पूरी तरह से प्रभावित होता है। नकली और गुणवत्ताहीन दवाओं का बढ़ता दायरा केवल पीड़ित लोगों के जीवन खतरे में नहीं होते हैंबल्कि स्वास्थ्य प्रणाली और चिकित्सा उद्योग की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है।

गुणवत्ताहीन दवा की पहचान करने की तकनीकी का न होना, ठोस कानून का आभाव के कारण नकली दवा का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। भारत में नकली और गुणवत्ताहीन दवा की बिक्री शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक होती है। भारत में नकली और गुणवत्ताहीन दवाओं का बढ़ता दायरा चिंता का विषय है। भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्माता और निर्यातक है। एशियन लाइट की रिपोर्ट के अनुसार-वैश्विक फार्मा बाजार में भारत की हिस्सेदारी 13 प्रतिशत है। भारत में बढ़ते नकली दवा से केवल न इंसानों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है बल्कि इससे भारत की वैश्विक स्तर पर दवा उद्योग में छवि भी धूमिल होती है। नकली और गुणवत्ताहीन दवाओं के प्रचलन से चिकित्सा पेशे और स्वास्थ्य प्रणाली से जनता का विश्वास भी घटता है।

स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है। मनुष्यों को स्वस्थ रहने के लिए उपचार की आवश्यकता भी होती है, लेकिन जब उपचार नकली और गुणवत्ताहीन दवाओं पर आधारित हो तो इंसानों का स्वास्थ्य पूरी तरह से प्रभावित होता है। नकली और गुणवत्ताहीन दवाओं का बढ़ता दायरा केवल पीड़ित लोगों के जीवन खतरे में नहीं होते हैंबल्कि स्वास्थ्य प्रणाली और चिकित्सा उद्योग की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है।

नकली दवा के रोकथाम के लिए कानूनी प्रावधानों में परिवर्तन करते हुए नकली दवाओं के उत्पादन और बिक्री में संलिप्त व्यक्तियों के लिए बहुत सख्त और दंड के साथ आर्थिक जुमार्ने का प्रावधान होना चाहिए। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और राज्य स्तर पर दवा नियामक संस्थानों को दवाओं के प्रति साप्ताहिक प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। सभी दवा कमानियों को सभी प्रकार के दवा उत्पाद पर ट्रैक और ट्रेस तकनीक का उपयोग के लिए सरकार द्वारा बाध्य किया जाना चाहिए ताकि मरीज नकली और असली दवाओं की पहचान आसानी से कर सकें। दवा की प्रामाणिकता जांचने के लिए मोबाइल एप और ऑनलाइन डेटाबेस की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

नकली और गुणवत्ताहीन दवाओं की रोकथाम के लिए वैश्विक स्तर पर एकजुट होकर समस्या का समाधान तलाश करना होगा। भारत को नकली दवाओं को रोकने के लिए बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना होगा। बढ़ती जनसंख्या, निर्धनता और महंगी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण लोगों को सस्ती और नकली दवाओं पर बाध्य होना पड़ता है। भारत को नाइजीरिया और अमेरिका की तकनीकी मेडिसेफर एवं ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की पहल करना चाहिए। यह तकनीकी नकली आपूर्ति श्रृंखला नजर रखती है। सख्त कार्रवाई से ही स्वस्थ भारत और सशक्त भारत का निर्माण होगा।

घूँघट की बगावत

05 जनवरी 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

आशा, उमंग व अभिलाषाओं के संग नूतन वर्ष '2025' का करें स्वागत

जीवन पथ की रोजमर्रा की छोटी व बड़ी खट्टी-मीठी यादों के साथ अंग्रेजी वर्ष 2024 की कैलेंडर से विदाई हो गयी है। दुनिया भर में जगह-जगह जबरदस्त धूमधाम के साथ विश्व के बहुत सारे देशों में अंग्रेजी नूतन वर्ष 2025 का जबरदस्त हर्षोल्लास उमंग के साथ स्वागत किया जा रहा है। हालांकि वैसे भी देखा जाएं तो अंग्रेजी नूतन वर्ष हो या हम सभी हिन्दूओं का प्यार नवसंवत्सर हो या देश व दुनिया भर में किसी भी अन्य देश व धर्म के नूतन वर्ष की शुरूआत का अवसर हो, हर एक व्यक्ति अपने बीतते हुए वर्ष की अपनी उपलब्धियों का बारीकी से आत्ममंथन करते हुए शुरू होने वाले नूतन वर्ष के लिए कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण नए लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक खास रणनीति बनाने का कार्य करता है, वह प्रयास करता है कि पूरे वर्ष उस रणनीति पर चलते हुए लक्ष्य को हासिल करने का कार्य करें। वैसे भी हर वर्ष के नूतन वर्ष की शुरूआत व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ नयी आशा, नयी उम्मीद की किरण लेकर के आती है। नूतन वर्ष का हर्षोल्लास वाला अवसर उत्साह और उम्मीद के सामंजस्य का एक बेहद ही अनमोल पल होता है, जो हम सभी के जीवन की दिशा व दशा बदलने में बेहद ही कारगर साबित हो सकता है। नूतन वर्ष जोशो-खरोश के साथ पारंपरिक व आधुनिक उत्सवों से परिपूर्ण जीवन में एक नयी ऊर्जा भरने वाला अवसर होता है, जो जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ ऐसी अनेकानेक छोटी व बड़ी खुशियां लेकर के आता हैं, जिनको बहुत सारे लोगों के द्वारा शब्दों में बयां करना आसानी से संभव नहीं होता है।

नूतन वर्ष का यह अवसर हमारे जीवन में अपनी मेहनत के दम पर अपनी गलतियों का सुधार करने का एक प्रेरणादायक अवसर होता है। यह हमें जीवन पथ पर चलते हुए नित कुछ नया सीखते हुए, कड़ी मेहनत करते हुए, कुछ नया सकारात्मक करने की प्रेरणा देता है और यह हम लोगों को अपने सर्वांगीण विकास पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देता है। हर किसी का नूतन वर्ष उससे जुड़े लोगों के जीवन में दृढ़ संकल्प के साथ सकारात्मकता का संचार करने को प्रेरित करता है। यह अवसर हम लोगों को बड़े-बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए फिर से एक नई शुरूआत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नूतन वर्ष हमें अपनी स्वयं की मौलिकता और प्रेरणा को जारी रखने के लिए पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान करता है।

नूतन वर्ष का अवसर आम व खास सभी वर्गों के लोगों के लिए अपने दुःख-दर्दों को भूलकर के जीवन में एक नयी पॉजिटिव पहल करने का अवसर होता है। इस महत्वपूर्ण दिन के साथ हम लोगों को अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में चले आ रहे कष्टों को भूलकर के एक नयी शुरूआत करते हुए जीवन को भयमुक्त करके सामान्य व खुशहाल बनाने के लिए फिर से एकबार पूरी ताकत के साथ प्रयास अवश्य करना चाहिए।

नूतन वर्ष पर हमें ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव, आपसी मनमुटाव भूलकर के यह अवश्य समझना चाहिए कि नूतन वर्ष उम्मीद की अनंत संभावनाओं की शुरूआत का अनमोल समय होता है। यह हमें अपने बुरे अतीत को पीछे छोड़ने और जीवन पथ पर आशावाद और दृढ़ संकल्प के साथ अपने भविष्य को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। इसलिए नूतन वर्ष के अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम जीवन के सार्थक लक्ष्य को निर्धारित करते हुए, उसके लिए काम करते हुए उसको हासिल करने का प्रयास करते हुए, इस नूतन वर्ष को बीते हुए पिछले वर्षों से बेहतर बनायेंगे। नूतन वर्ष का अवसर जश्न मनाते हुए एकता, कृतज्ञता और दृढ़ता की प्यार मोहब्बत की जीवन में अहमियत की याद दिलाता है। इसलिए नूतन वर्ष की शुरूआत के साथ हम यह संकल्प लें कि इस वर्ष अपने द्वारा तय किये गये गोल या लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम दिन-रात एक करके कार्य करेंगे। नूतन वर्ष पर हमें अपने व अपनों के विकास के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, तब ही देश का विकास होगा यह समझ कर के उस लक्ष्य के लिए कार्य करना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि अनमोल रिश्तों को प्यार की झप्पी से संजोकर, घर-परिवार, देश व दुनिया में सकारात्मक योगदान देने का प्रयास करने की शानदार पहल की शुरूआत करनी चाहिए।

इसलिए अंग्रेजी नूतन वर्ष पर मैं अपने उपरोक्त शब्दों में छिपी सकारात्मक भावना के साथ यह उम्मीद करता हूँ कि इस वर्ष हम सभी देशवासी आपसी मनमुटाव को भूलकर फिर से अपने जीवन की एक नई शानदार शुरूआत करेंगे और परिवार व देश निर्माण के लिए दिन-रात एकजुट होकर के कार्य करेंगे। वैसे भी हममें से

हर किसी का नूतन वर्ष उससे जुड़े लोगों के जीवन में दृढ़ संकल्प के साथ सकारात्मकता का संचार करने को प्रेरित करता है। यह अवसर हम लोगों को बड़े-बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए फिर से एक नई शुरूआत करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

अधिकांश लोग हमेशा यह चाहते है कि नूतन वर्ष की एक बहुत अच्छे से शुरूआत हो और हम लोग उज्जवल भविष्य की आशा में सकारात्मक ऊर्जा व उमंग, हर्षोल्लास के साथ जीवन पथ पर निरंतर चलते रहे। वैसे भी देखा जाएं तो अधिकांश लोगों की मान्यता है कि नूतन वर्ष के प्रथम दिन सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जीवन का एक बेहद महत्वपूर्ण दिन होता है, इसलिए हम इस दिन उसके ही अनुरूप अपनी दिनचर्या को निर्धारित करते हुए जीवन पथ पर चलने का प्रयास करते हैं। हमें उम्मीद है कि यह नूतन वर्ष एक नई उम्मीद, नई आशाएं, नई खुशियां, जीवन में नई उमंग, नये लक्ष्य व हमारे जीवन के लिए जरूरी सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है। नूतन वर्ष के प्रथम दिन हम लोगों को संकल्प लेना होगा कि बीते वर्ष की खट्टी-मीठी व कड़वी यादों को दिलों में संजोकर उनसे सबक लेकर जीवन पथ पर पूर्ण सकारात्मक ऊर्जा के साथ अग्रसर होकर तय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए दिल से प्रयास करेंगे। नूतन वर्ष पर हम लोगों को अपने-अपने आराध्य सर्वशक्तिमान ईश्वर का तहेदिल से आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि उनके ही आशिर्वाद से हम सभी के जीवन में एकबार फिर से नूतन वर्ष उदित होने का यह अवसर आया है, जिस दिन के लिए हम हमेशा ऋणी रहेंगे। नूतन वर्ष में हम सभी के जीवन में नव आशा, नव उत्साह, नव हर्ष हो, जीवन में नयी ताजगी हो, एक नई उमंग हो, अपनों का हर पल हर क्षण संग हो, जीवन पथ के प्रगति के पथ पर चलते हुए हर्ष हो, नूतन वर्ष नई आशाओं से पूर्ण शोभित हो, हम लोग बेहद गंभीर समस्याओं से मुक्त होकर जल्द से जल्द तनाव से मुक्त हों, हम सभी देशवासियों के जीवन में इन्हीं सकारात्मक बदलाव वाली मंगलकामनाओं के साथ नई आशाएँ व नई अभिलाषाएँ के साथ नूतन वर्ष '2025' बहुत ही शानदार ढंग से उदित हो।

– दीपक कुमार त्यागी

नए साल का जश्न भारत के साथ ही पूरी दुनिया में नए साल का जश्न शुरू हो गया है। कड़कड़ती ठंड में भी लोग घरों से बाहर निकल कर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। देश के कोने-कोने में आतिशबाजी कर साल 2025 का ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है। साल 2024 खत्म हो चुका है। नए साल 2025 की शुरूआत हो चुकी है। पूरी दुनिया में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। दुनिया के पूर्वी कोने से नए साल का आरंभ हुआ। दुनियाभर में लोग नए साल का जश्न में मना रहे हैं।

केरल में नए साल का जश्न कुछ इस तरह मनाया गया

कोलकाता में नव वर्ष 2025 का जश्न मनाते लोग

आशा है नव साल की, सुखद बने पहचान॥

●●●

खिली-खिली हो जिंदगी, महक उठे अरमान।
आशा है नव साल की, सुखद बने पहचान॥

●●●

दर्द दुखों का अंत हो, विपदाएँ हो दूर।
कोई भी न हो कहीं, रोने को मजबूर॥

●●●

छेड़ रही है प्यार की, मीठी-मीठी तान।
नए साल के पँख पर, खुशबू भरे उड़ान॥

●●●

बीत गया ये साल तो, देकर सुख-दुःख मीत।
क्या पता? क्या है बुना? नई भोर ने गीत॥

●●●

माफ करे सब गलतियाँ, होकर मन के मीत।
मिटे सभी की वेदना, जुड़े प्यार की रीत॥

●●●

जो खोया वह सोचकर, होना नहीं उदास।
जब तक साँसे हैं मिली, रख खुशियों की आस॥

●●●

पिंजड़े के पंछी उड़े, करते हम बस शोक।
जाने वाला जायेगा, कौन सके है रोक॥

●●●

पथ के शूलों से डरे, यदि राही के पाँव।
कैसे पहुँचेगा भला, वह प्रियतम के गाँव॥

●●●

रुको नहीं चलते रहो, जीवन है संघर्ष।
नीलकंठ होकर जियो, विष तुम पियो सहर्ष॥

●●●

दुःख से मत भयभीत हो, रोने की क्या बात।
सदा रात के बाद ही, हँसता नया प्रभात॥

●●●

चमकेगा सूरज अभी, भागेगा अँधियार।
चलने से कटता सफर, चलना जीवन सार॥

●●●

काँटें बदले फूल में, महकेंगें घर-द्वार।
तपकर दुःख की आग में, हमको मिले निखार॥

●●●

-प्रियंका सौरभ

बांग्लादेशी घुसपैठियों की पकड़-धकड़ करने से विशेष लाभ नहीं मिलने वाला

इन दिनों दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें निकाल बाहर करने का अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत अभी तक दस बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी वापस नहीं भेजा जा सका है। कहना कठिन है कि दिल्ली पुलिस का अभियान कब तक जारी रहेगा और कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाला जा सकेगा, लेकिन यह ध्यान रहे कि पहले भी दिल्ली में इस तरह का अभियान चल चुका है। वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था।

दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान का अभियान चल निकला है। वहां भी अतीत में इस तरह का अभियान चला था और उसका नतीजा भी ढाक के तीन पात वाला रहा था। यही कहानी असम की भी है, जहां इन दिनों बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की कवायद की जा रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और राज्य ऐसा करें, लेकिन यह तय है कि कुछ राज्य ऐसा नहीं भी करने वाले, जैसे कि बंगाल। इसी तरह झारखंड में भी यह काम नहीं होने वाला।

विधानसभा चुनावों के समय झारखंड सरकार ने भाजपा के इन आरोपों को खंडन किया था कि बंगाल के रास्ते भारत में घुस आए बांग्लादेशी राज्य में बस गए हैं। उसने यह सवाल भी पूछा था कि अगर ऐसा हो रहा है तो केंद्र सरकार ऐसा होने कैसे दे रही है? केंद्र सरकार इस सवाल का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी थी।

एक समय अवैध रूप से भारत आने वाले बांग्लादेशी बंगाल, असम, त्रिपुरा आदि सीमावर्ती राज्यों में ही अपना ठिकाना बनाना पसंद करते थे, लेकिन अब वे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद से लेकर देश के हर हिस्से में मिल जाते हैं। किसी के लिए कहना कठिन है कि उनकी संख्या कितनी है? अलग-अलग आंकड़ों में उनकी संख्या भिन्न-भिन्न बताई जाती रही है। सही आंकड़ा इसलिए नहीं, क्योंकि केंद्र या राज्य सरकारों के पास ऐसा तंत्र ही नहीं, जो यह रेखांकित कर सके कि कितने बांग्लादेशी अवैध

रूप से आए और वे कब से कहां रह रहे हैं।

कुछ लोग दावा करते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या करोड़ों में है और कुछ के अनुसार लाखों में। बांग्लादेशी घुसपैठियों की तरह कोई यह भी नहीं बता सकता कि देश में अवैध रूप से आए रोहिंग्या कितने हैं। जो बताया जा सकता है, वह यह कि वे पूर्वी हिस्से से देश में घुसे और जम्मू एवं हैदराबाद तक जाकर बस गए। यह सहज ही समझा जा सकता है कि किसी ने उनकी मदद की होगी। प्रबल आशंका यही है कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की घुसपैठ कराने और उन्हें असली-नकली पहचान पत्रों से लैस करके भारतीय नागरिकों का चोला पहनाने वाले अब भी सक्रिय होंगे। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर केवल इसलिए नहीं निकाला जाना चाहिए कि शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश भारतीय हितों के खिलाफ काम कर रहा है। यह काम इसलिए भी होना चाहिए कि वे संसाधनों पर बोझ बनने के साथ ही देश की सुरक्षा के लिए खतरा भी बन रहे हैं। बांग्लादेशी हों या रोहिंग्या, वे अपनी स्पष्ट पहचान के साथ शरणार्थी के रूप में तो भारत में रह सकते हैं, लेकिन घुसपैठियों के रूप में नहीं।

एक ऐसे समय जब दुनिया भर में और विशेष रूप से पश्चिमी देशों में अवैध रूप से आए लोगों के खिलाफ आवाज उठ रही है और अमेरिका में तो डोनाल्ड ट्रंप यह आवाज उठाकर चुनाव भी जीत गए, तब इसका कोई औचित्य नहीं कि भारत घुसपैठियों के प्रति ढुलमुल बना रहे या फिर उनकी पहचान का अभियान आधे-अधूरे मन से चलाया जाए। जब किसी समस्या के समाधान के लिए कामचलाऊ कदम उठाए जाते हैं तो वे केवल नाकाम ही नहीं होते, बल्कि समस्या बने तत्वों का दुस्साहस भी इससे बढ़ता है। इसलिए बढ़ता है, क्योंकि उन्हें संदेश जाता है कि समस्या का समाधान करने वाले गंभीर नहीं। यह समझा जाए तो बेहतर कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ देशव्यापी अभियान सघन तरीके से चलना चाहिए।

इससे इनकार नहीं कि बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है, लेकिन आखिर केंद्र सरकार इस घुसपैठ को रोक क्यों नहीं पा रही है? कारण जो भी हो, किसी एक या दो-तीन राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पकड़-धकड़ करने से विशेष लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि घुसपैठिये पड़ोसी राज्यों में आसानी से जा सकते हैं। क्या यह सहज स्वाभाविक नहीं कि दिल्ली पुलिस के अभियान को देखते हुए बांग्लादेशी घुसपैठिये उत्तर प्रदेश और हरियाणा खिसक जाएं? ऐसा होने का अंदेशा इसलिए भी है, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने के किसी अभियान की तुलना में उनकी घुसपैठ कराने वाला तंत्र कहीं अधिक कारगर है।

यह तंत्र बांग्लादेशी नागरिकों को केवल भारत में घुसने में ही मदद नहीं करता, बल्कि उनके लिए सुरक्षित ठिकाने भी उपलब्ध कराता है। इतना ही नहीं, यह तंत्र उन्हें असली-नकली आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्रों से लैस भी करता है। बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से भारत की सीमा में जैसे ही प्रवेश करते हैं, उन्हें आधार कार्ड उपलब्ध करा दिया जाता है। यह तंत्र केवल बांग्लादेश से लगती सीमा पर ही सक्रिय नहीं है।

गत दिवस दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा, जो राजधानी में बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार कार्ड के साथ मतदाता पहचान पत्र तैयार कर रहा था।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित।

संपादकः पंकज धर द्विवेदी

संपर्क सूत्र : ghoonghatkibagawat37@gmail.com